www.rashtratak.com twitter.com/rashtratak facebook.com/rashtratak @rashtratak

मूल्य ₹ 89

राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका

नई दिल्ली से प्रकाशित

राष्ट्र समाज

RNI No.: DELHIN/2014/56304

वर्ष-13 ▪ अंक-03 ▪ जून 2026 ▪ पृष्ठ संख्या 52

आपकी आवाज़...

राष्ट्र निर्माण और सामाजिक समरसता का महाकुंभ 06

परीक्षा नहीं, भविष्य लीक हुआ है 22

ढहते आशियाने बेबस चीखें

कोयला मंत्रालय
MINISTRY OF
COAL

कोल इण्डिया
Coal India

CCL

Fuelling Sustainable Growth

हमारा प्रयास : हितधारकों, ग्रामीणों एवं श्रमिकों का सर्वांगीण विकास

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

CENTRAL COALFIELDS LIMITED

(A Govt. of India Undertaking / A Subsidiary of Coal India Limited)

Darbhanga House, Ranchi - 834001 (Jharkhand)

संपादकीय

> 'सीयूईटी-यूजी में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण हजारों छात्र और अभिभावक परेशान हुए, जिससे एनटीए की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल उठे हैं।

प्रमोद तिवारी संपादक

कब सुधरेगी एनटीए की व्यवस्था?

'सीयूईटी-यूजी में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण हजारों छात्र और अभिभावक परेशान हुए, जिससे एनटीए की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल उठे हैं। पहले नीट और अन्य परीक्षाओं में भी विवाद सामने आ चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सुधारात्मक कदम काफी नहीं, बल्कि जवाबदेही और मजबूत रोकथाम व्यवस्था जरूरी है।' **एक और एग्जाम, एक और खामी** - नैशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के साथ यह कहानी बार-बार दोहराई जा रही है। सीयूईटी-यूजी में जिस तरह की अव्यवस्था देखने को मिली, वह हताश करने वाली है। सबसे ज्यादा निराशाजनक बात यह है कि एजेंसी अपने वादों पर खरी नहीं उतर पा रही और इससे उबरने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। फिर से एग्जामः देशभर के विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली सीयूईटी-यूजी में तकनीकी दिक्कतों की वजह से स्टूडेंट्स और उनके पैरंट्स घंटों परेशान रहे। कई जगह परीक्षा देरी से शुरू हुई और कई जगह हो ही नहीं पाई। एनटीए ने 3765 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एग्जाम कराने की बात कही है। एजेंसी का गड़बड़ियों को स्वीकार करना ठीक है, लेकिन असली सवाल है कि ऐसा बार-बार क्यों हो रहा है।

पहले मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट रद्द करना पड़ा, क्योंकि पेपर लीक हो गए थे। इसके बाद सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर विवाद उठा। ये दोनों मामले अभी तक हल नहीं हुए थे और सीयूईटी-यूजी का मसला खड़ा हो गया। इससे एक दिन पहले, 29 मई को ही नीट-यूजी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और उसमें अदालत ने जो टिप्पणियां कीं, उन पर अमल करने की जरूरत है। एनटीए की तरफ से उठाए गए ज्यादातर कदम सुधारात्मक होते हैं, जिन पर ध्यान गड़बड़ी होने के बाद जाता है, जबकि जरूरत है पहले से बचाव के उपाय अपनाने की। इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए और जो जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा सकते, उन पर कार्रवाई हो।

परीक्षा दोबारा करा देना, रीशेड्यूलिंग या ग्रेस मार्क वगैरह कभी-कभार तो ठीक हैं, लेकिन ये आदत नहीं बन सकते। किसी परीक्षा के लिए एक स्टूडेंट सालभर तैयारी करता है। जितना दबाव उस पर होता है, उतना ही उसके पैरंट्स पर भी। एनटीए को बनाया गया था ताकि देश की प्रमुख परीक्षाएं व्यवस्थित ढंग से कराई जा सकें। अभी तक एजेंसी इसमें सफल नहीं हो पाई है। आरोप है कि स्टूडेंट्स की परेशानियों को ठीक से नहीं समझा जाता, खासकर सेंटर अलॉटमेंट में। केवल किसी तरह एग्जाम करा देने से एनटीए का काम पूरा नहीं हो जाता। इससे लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा है, तो संवेदनशीलता भी जरूरी है। 21 जून को नीट-यूजी दोबारा होनी है और एजेंसी का दावा है कि इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उम्मीद है यह काम कर जाए, क्योंकि छात्रों के भरोसे का बार-बार टूटना अच्छा नहीं है।

> इसके बाद सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर विवाद उठा। ये दोनों मामले अभी तक हल नहीं हुए थे और सीयूईटी-यूजी का मसला खड़ा हो गया। इससे एक दिन पहले, 29 मई को ही नीट-यूजी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और उसमें अदालत ने जो टिप्पणियां कीं, उन पर अमल करने की

राष्ट्र समाज

RNI No.: DELHIN/2014/56304 ₹ 89

वर्ष-13, अंक-03, जून 2026

पृष्ठ संख्या-52

प्रेरणा स्रोत

स्व.पुरुषोत्तम तिवारी, स्व.एन.के. लोहिया

मुख्य संरक्षक

विनीत कुमार गुप्ता

संरक्षक

बालमुकुन्द ओझा, त्रिवेणी नाथ तिवारी, हरिशंकर दुबे, संजीव गोयल

संपादक

प्रमोद तिवारी

सह संपादक

सुशील ओझा,आनंद दीप श्रीवास्तव, आचार्य श्रीकांत तिवारी

सलाहकार समिति

अशोक गुप्ता (सकरनी) सभाजीत पांडेय, एम. के त्रिपाठी, विपिन गोयल, संजीव गोयल, ऋषि मित्तल

कानूनी सलाहकार

अधिवक्ता बीपी पाण्डेय, गौरव भारद्वाज

ब्यूरो चीफ

किरन ओझा, पुनीत मिश्र, अखिलेश शर्मा, बसंत भट्ट, हरीश तिवारी, अशोक शर्मा

प्रसार

पुनीत मिश्रा-9911882767

विज्ञापन

आशुतोष तिवारी- 83682 72439

डिजाइन व प्रोडक्शन

एनएम मीडिया सॉल्यूशंस, दिल्ली

संपादकीय कार्यालयः मकान नं. 2, पहली मंजिल, पश्चिम एन्क्लेव, रोहतक रोड, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087

दूरभाषः 011-40105158, 9953772767

वेब : www.railhumrahi.com

ई-मेल : rastrasamaj@gmail.com

स्वत्वाधिकारी अपराइट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक प्रमोद तिवारी द्वारा एस-561, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-2, नई दिल्ली-84 से प्रकाशित तथा मित्तल इण्टरप्राइजेज 2016 गोकुल शाह स्ट्रीट सीता राम बाजार दिल्ली-06 से मुद्रित।

***संपादकः प्रमोद तिवारी ***

लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित

नोटः पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है, तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद का निपटारा दिल्ली न्यायालय में ही किया जायेगा। राष्ट्र समाज पत्रिका में प्रकाशित सभी पद अवैतनिक हैं। पत्रिका के लिए भेजी गयी सामग्री के प्रकाशन पर पूर्व अनुबंध के बिना कोई भी पारिश्रमिक देने की व्यवस्था नहीं है।

08

ढहते आशियानों की बेबस चीखें

देश की राजधानी दिल्ली का शालीमार बाग इलाका। अमूमन यह क्षेत्र अपनी हरी-भरी वादियों, ...

20

'कॉकरोच जनता पार्टी' के उभार के मायने

भारतीय राजनीति में सोशल मीडिया और मीम्स अब केवल मनोरंजन या समय काटने का साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि वे व्यवस्था के खिलाफ पनप रहे एक बहुत बड़े और गहरे असंतोष को व्यक्त करने का सबसे धारदार हथियार बन चुके हैं।

22

परीक्षा नहीं, भविष्य लीक हुआ है

भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं अब केवल करियर का माध्यम नहीं रह गई हैं; वे करोड़ों परिवारों की आकांक्षाओं, सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक भविष्य का केंद्र बन चुकी हैं। यही कारण है कि जब राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 को कथित...

अंदर

24

बंगाल की हिंसा लोकतंत्र पर धब्बा

पश्चिम बंगाल में हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनावों के बाद जिस प्रकार हिंसा, हत्याओं, आगजनी और राजनीतिक प्रतिशोध की घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने केवल राज्य की शांति को ही नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को भी आहत किया है।

26

राहुल-अखिलेश पर टिकी 2029 की राजनीति

2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब देश ने विपक्षी गोलबंदी का एक महा-प्रयोग देखा था, तब उसका नाम था 'इंडिया गठबंधन' । यह प्रयोग बिना संदेह बड़ा था। 26 प्रमुख विपक्षी दलों को एक छत के नीचे लाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी।

46

शरवरी और वेदांग के 'मस्कारा' ने इंटरनेट पर मचाया धमाल

इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा का रोमांटिक ट्रैक मस्कारा दर्शकों के दिलों को छूने में कामयाब रहा है और देखते ही देखते साल के सबसे चर्चित गानों में शामिल हो गया है...

राष्ट्र निर्माण और सामाजिक समरसता

अग्रवाल सम्मेलन का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न

@ राष्ट्र समाज

राजधानी नई दिल्ली का प्रतिष्ठित 'ले मेरिडियन' होटल का भव्य सभागार 18 मई 2026 की शाम एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना। अवसर था 'अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन' के राष्ट्रीय अधिवेशन और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का। देशभर से जुटे अग्रवाल समाज के प्रबुद्धजीवियों, दिग्गज उद्योगपतियों, कर्मठ समाजसेवियों और विभिन्न क्षेत्रों की नामचीन हस्तियों की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को एक बेहद गरिमामय और प्रेरणादायी महाकुंभ में बदल दिया। राष्ट्रीय एकता, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक चेतना के रंग में रंगे इस अधिवेशन का उद्देश्य न सिर्फ नई कार्यकारिणी को जिम्मेदारी सौंपना था, बल्कि आधुनिक दौर में महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों को पुनर्जीवित करना भी था।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष माननीय सांसद श्री ओम बिरला ने दीप प्रज्वलन कर समारोह की शुरूआत की। उन्होंने नव-निर्वाचित राष्ट्रीय पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ

दिलाई। अपने संबोधन में समाज को एक नई दिशा देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांत, समानता, समावेशिता, सहयोग और सामूहिक भागीदारी, आज के आधुनिक युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। श्री बिरला ने समाज की सराहना करते हुए कहा, 'महाराजा अग्रसेन जी की प्रेरणा से अग्रवाल समाज ने सेवा, सहयोग और सामाजिक समरसता को हमेशा राष्ट्रहित से ऊपर रखा है। समाज का ऐतिहासिक दर्शन 'एक ईंट और एक रुपया' आज के वैश्विक दौर में भी समाजवाद और जनकल्याण का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी इस गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और सेवाभावी संकल्पों के साथ और आगे ले जाएगी।

स्वामी बालकानंद गिरि जी महाराज का मिला आध्यात्मिक सान्निध्य

समारोह को अपनी दिव्य उपस्थिति से आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महा मंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री

का महाकुंभ

सेवा का भाव ही जीवन का असली उद्देश्यः विनीत कुमार गुप्ता

समारोह के दौरान संस्था के वरिष्ठ स्तंभ विनीत कुमार गुप्ता (लोहिया) ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने सम्मेलन द्वारा किए जा रहे कार्यों को अतुलनीय बताते हुए कहा कि सेवा का भाव ही मानव जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। यह संगठन देश भर के अग्रवाल समाज को एक साझा मंच पर लाने, शिक्षा का प्रसार करने व समाज की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर काम कर रहा है।

बालकानंद गिरि जी महाराज ने। पूज्य गुरुदेव के सान्निध्य ने पूरे माहौल को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। इस मौके पर आयोजकों द्वारा गुरुदेव को प्रतीक चिह्न और अंगवस्त्र भेंट कर उनका आत्मीय अभिनंदन किया गया। अपने ओजस्वी और विचारोत्तेजक उद्बोधन में पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अग्रवाल समाज केवल व्यापार में ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण, लोककल्याण और वैदिक संस्कारों को बचाने में हमेशा आगे रहा है। उन्होंने विशेष रूप से युवा पीढ़ी का आह्वान करते हुए कहा कि आज के समय में युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों, नैतिक मूल्यों और संगठन की भावना से जुड़े रहने की सख्त जरूरत है, क्योंकि समाज की मजबूती से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है।

देशभर से जुटे प्रबुद्ध जनों का महासमागम

इस ऐतिहासिक अधिवेशन की सफलता के पीछे उन तमाम दिग्गजों की उपस्थिति रही जो देश के अलग-अलग राज्यों से इस मंच पर एकजुट हुए थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप सेः

- **नंद किशोर अग्रवाल, के. के. अग्रवाल, बसंत कुमार मित्तल, गोपाल गोयल**
- **विनोद कुमार अग्रवाल, नत्थू राम जैन, सत्य भूषण जैन, पूरण मल अग्रवाल**
- **राजेंद्र अग्रवाल, श्री कुलभूषण गोयल, प्रेम चंद मंगल, प्रमोद जैन, मनोज जिंदल और अमित अग्रवाल**
- **सहित सैकड़ों गणमान्य लोगों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई व संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया।**

अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का यह राष्ट्रीय अधिवेशन केवल एक औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, बल्कि यह आधुनिक भारत के विकास में अग्रवाल समाज की भागीदारी का एक नया रोडमैप था। जब समाज की नई कार्यकारिणी, देश के शीर्ष नेतृत्व (लोकसभा अध्यक्ष) के विजन और पूज्य संतों के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ती है, तो समाज और राष्ट्र का कल्याण निश्चित हो जाता है। यह आयोजन आने वाले समय में अग्रवाल समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

@ प्रमोद तिवारी

ढहते आशियानों की बेबस चीखें

बीते दिनों इस इलाके ने एक ऐसा मंजर देखा, जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया। आसमान में धूल का एक ऐसा गुबार था जो थामे नहीं थम रहा था, कानों के परदे फाड़ देने वाली आधा दर्जन बुलडोजरों की भीषण गड़गड़ाहट थी, और उस गड़गड़ाहट के बीच से छनकर आ रही थीं औरतों, बच्चों और बिलखते बुजुर्गों की चीखें। सालों की यादें, पाई-पाई जोड़कर खड़े किए गए आशियाने और खून-पसीने की पूरी कमाई महज कुछ ही घंटों में मलबे के ढेर में तब्दील कर दी गई।

देश की राजधानी दिल्ली का शालीमार बाग इलाका। अमूमन यह क्षेत्र अपनी हरी-भरी वादियों, रिहायशी सोसायटियों और चमचमाती सड़कों के लिए जाना जाता है। लेकिन बीते दिनों इस इलाके ने एक ऐसा मंजर देखा, जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया। आसमान में धूल का एक ऐसा गुबार था जो थामे नहीं थम रहा था, कानों के परदे फाड़ देने वाली आधा दर्जन बुलडोजरों की भीषण गड़गड़ाहट थी, और उस गड़गड़ाहट के बीच से छनकर आ रही थीं औरतों, बच्चों और बिलखते बुजुर्गों की चीखें। सालों की यादें, पाई-पाई जोड़कर खड़े किए गए आशियाने और खून-पसीने की पूरी कमाई महज कुछ ही घंटों में मलबे के ढेर में तब्दील कर दी गई।

सेंट्रल जिला प्रशासन के भारी सुरक्षा अमले, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के कड़े पहरे के बीच जब 'मधुमिलन चौराहे से लेकर छावनी' तक के इलाके को चारों तरफ से घेरा गया, तो वहां रह रहे 150 से अधिक गरीब परिवारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरकारी और कानूनी पन्नों पर जिसे 'अतिक्रमण हटाओ अभियान' का नाम देकर फाइलों में बंद कर दिया गया, वह असल में कई मासूम जिंदगियों के सिर से उनकी छत, उनकी अस्मिता और उनके सुनहरे सपनों को हमेशा-हमेशा के लिए छीन ले जाने वाला एक प्रशासनिक कहर साबित हुआ।

आंसुओं का सैलाब

प्रशासनिक अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र सिंह परिहार के नेतृत्व में की गई इस बड़ी कार्रवाई के पीछे एक बड़ा विजन बताया जा रहा है। सरकारी दावों के मुताबिक, दिल्ली के मास्टर प्लान के तहत इस इलाके में एक 30 मीटर चौड़ी सड़क कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है।

वर्तमान स्थिति यह थी कि इस खास हिस्से पर सड़क बेहद संकरी हो चुकी थी, जिसके कारण पूरे शालीमार बाग और आसपास के इलाकों में घंटों भीषण ट्रैफिक जाम लगा रहता था। इतना ही नहीं, मानसून के समय यहाँ ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होने से जलभराव की एक गंभीर समस्या पैदा हो जाती थी, जिससे लाखों राहगीर परेशान होते थे।

विकास के इस बड़े और आधुनिक विजन के आगे प्रशासन को 8 एकड़ की इस सरकारी जमीन को हर हाल में खाली कराना था। प्रशासनिक सर्वे व मैपिंग के बाद यह पाया गया कि करीब 120 से अधिक पक्के और अर्ध-पक्के ढांचे सीधे तौर पर इस सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन रहे थे। इन सभी चिन्हित ढांचों को गिराने के लिए प्रशासन द्वारा बकायदा कानूनी नोटिस व चेतावनी जारी

की गई थी, जिसकी म्याद खत्म होते ही बुलडोजर गरजे। लेकिन इस 'आधुनिक विकास' की वेदी पर जो बलि चढ़ी, वह उन गरीबों की थी जो पिछली कई पीढ़ियों से यहां अपना घर बसाकर रह रहे थे। एक तरफ जहां प्रशासन का सख्त तर्क है कि इस विवादित भूमि का अधिग्रहण सरकार द्वारा साल 1980 में ही कर लिया गया था और उस समय के मूल भूस्वामियों को नियमों के तहत उचित मुआवजा भी दिया जा चुका था, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के मौजूदा बाशिंदों का दर्द कुछ और ही कहानी बयां करता है। मलबे के ढेर पर बैठकर रोती हुई एक बुजुर्ग महिला ने भराई आवाज में कहाः 'हमें प्रशासनिक अफसर कहते हैं कि हमारे पास कागज नहीं हैं। लेकिन साहब, हम यहाँ पिछले 35-40 साल से रह रहे हैं। हमारे बच्चे यहीं पैदा हुए, उनकी शादियाँ यहीं हुईं, हमारे बुजुर्ग यहीं मर गए। हमारे पास वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, हम हर महीने सरकार को टैक्स और बिल देते आए हैं, फिर हम रातों-रात इस जमीन पर 'अवैध' और पराये कैसे हो गए? जब वोट लेना होता है तो हम वैध नागरिक बन जाते हैं, और जब सड़क बनानी होती है तो हम कीड़े-मकोड़े की तरह उजाड़ दिए जाते हैं।'

अदालत से हाथ लगी मायूसी

तोड़फोड़ अभियान का सबसे स्याह और दर्दनाक पहलू यह रहा कि इन बेबस परिवारों को देश की सबसे बड़ी अदालतों से भी कोई तात्कालिक राहत या ढाल नहीं मिल सकी। जब जिला प्रशासन ने जमीन खाली करने के सख्त नोटिस थमाए, तो डूबते को तिनके का सहारा ढूंढते हुए करीब 157 निवासियों ने सामूहिक रूप से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट के सख्त निर्देश पर प्रशासन ने सभी कब्जाधारियों की व्यक्तिगत रूप से विस्तृत और लंबी सुनवाई भी की। लेकिन, कानूनी दांव-पेंचों और सरकारी भू-राजस्व के पुराने दस्तावेजों के मोर्चे पर ये गरीब और अनपढ़ लोग टिक नहीं सके। इस पूरी कानूनी स्क्रूटनी के दौरान एक भी निवासी ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण पत्र या खसरा-खतौनी नहीं दिखा सका जो सरकारी दस्तावेजों में उन्हें उस जमीन का 'वैध मालिक' साबित कर सके। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कब्जाधारियों को 30 मई तक स्वेच्छा से जगह खाली करने का अंतिम और कड़ा आदेश दे दिया। इसके बाद, आखिरी उम्मीद के साथ पीड़ित पक्ष देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं

मास्टर प्लान के नाम पर 150 से अधिक गरीब परिवारों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के सड़क पर फेंक देना सरासर तानाशाही और अन्याय है। कानून का उपयोग नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए होना चाहिए, उन्हें उजाड़ने के लिए नहीं। हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि जब तक इन बेघर हुए परिवारों के लिए पक्के मकानों या उचित पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक इनके रहने, टेंट और भोजन का पूरा जिम्मा जिला प्रशासन खुद उठाए।

विजेंद्र गुप्ता
विपक्ष के नेता

मास्टर प्लान और अतिक्रमण हटाने के नाम पर हैदरपुर और शालीमार बाग में गरीबों के आशियाने उजाड़ना बेहद शर्मनाक है। जब इन घरों में बिजली-पानी के कनेक्शन दिए जा रहे थे, तब प्रशासन कहां था? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने ही क्षेत्र के गरीबों को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम रही हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस बेदखली से प्रभावित हुए प्रत्येक परिवार को तुरंत ₹1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए व उनके पक्के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

देवेंद्र यादव

कांग्रेस नेता

मिली; शीर्ष अदालत ने भी स्थापित कानूनों और मास्टर प्लान की अनिवार्यता को देखते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। दोनों अदालतों के आदेश का कानूनी कवच पहनकर प्रशासन ने बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत के साथ कार्रवाई शुरू कर दी।

किसी भी प्रकार के हिंसक विरोध प्रदर्शन या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति से निपटने के लिए इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स की कई कंपनियां तैनात की गई थीं। डीसीपी और एसीपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी खुद धूप में खड़े होकर स्थिति की निगरानी कर रहे थे, और सुरक्षा के लिहाज से पूरे प्रभावित जोन की घेराबंदी करके सभी रास्तों को सील कर दिया गया था, ताकि कोई बाहरी सामाजिक संगठन या हमदर्द अंदर न आ सके।

'विकास जरूरी'

यह पूरा इलाका राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का खुद का विधानसभा क्षेत्र है। अपने ही क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर लोगों के आशियाने उजड़ने और मलबे में तब्दील होने की इस घटना पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरा दुख और चिंता व्यक्त की है। उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन बनाने की वकालत करते हुए अपना पक्ष रखा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पूरे घटनाक्रम पर कहाः 'शालीमार बाग में जो कुछ भी हुआ, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और हृदयविदारक है। दिल्ली के विकास के लिए, ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए और मास्टर प्लान के तहत सड़कों का चौड़ीकरण करना प्रशासनिक रूप से अनिवार्य हो सकता है, और हम अदालतों के आदेशों का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन एक चुनी हुई सरकार की मुखिया होने के नाते मेरा यह स्पष्ट मानना है कि विकास की कोई भी परियोजना गरीबों की चीखों और उनकी लाशों पर खड़ी नहीं होनी चाहिए। कानून की आड़ में मानवीय संवेदनाओं को इस तरह बेरहमी से कुचला नहीं जा सकता। उन्होंने आगे कहा, 'प्रशासन को इस डिमोलिशन ड्राइव को अंजाम देने से पहले इन 150 से अधिक परिवारों के पुनर्वास की एक ठोस और मानवीय योजना तैयार करनी चाहिए थी। आप किसी को रातों-रात खुले आसमान के नीचे, इस तपती गर्मी और आने वाले मानसून के भरोसे नहीं छोड़ सकते। मैंने तुरंत संबंधित अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि इन बेघर हुए परिवारों के लिए तत्काल प्रभाव से अस्थायी शेल्टर होम, खाने-पीने व दवाओं की व्यवस्था की जाए। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने का

क्या गरीबों के साथ न्याय हुआ?

एक निष्पक्ष पत्रकारिता के नजरिए से यदि हम इस पूरी घटना का विश्लेषण करें, तो कई ऐसे तीखे सवाल खड़े होते हैं जो हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था, नौकरशाही और न्याय प्रणाली को कटघरे में खड़ा करते हैं। यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या कानून की अंधी और सूखी व्याख्या में हम एक समाज के रूप में अपनी संवेदनाएं पूरी तरह खो चुके हैं?

पुनर्वास की नीति पर इतनी आपराधिक चुप्पी क्यों?

भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार देता है, जिसमें सिर पर एक बुनियादी छत होना भी शामिल है। अगर अदालती आदेश के तहत इन घरों को गिराना जरूरी भी था, तो प्रशासन ने बुलडोजर चलाने से पहले इन परिवारों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की व्यवस्था क्यों नहीं की? गरीबों को बेघर करके सड़कों को चौड़ा करना ही एकमात्र 'विकास' है?

दशकों तक सोती रही व्यवस्था अचानक कैसे जागी?

अगर यह पूरी जमीन साल 1980 से ही सरकारी थी, तो पिछले 40 से 45 सालों से स्थानीय प्रशासन, नगर निगम (दिल्ली नगर निगम), लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट और स्थानीय पुलिस क्या कर रहे थे? जब ये गरीब लोग वहां अपनी गाढ़ी कमाई से एक-एक ईंट जोड़कर पक्के मकान बना रहे थे, तब उन्हें शुरूआती दौर में ही क्यों नहीं रोका गया? क्या तब भ्रष्टाचार के तहत आंखें मूंद ली गई थीं?

वैध सुविधाओं व अवैध आशियानों का विरोधाभास

इन तथाकथित 'अवैध' मकानों में सरकारी महकमों द्वारा बिजली के लीगल कनेक्शन दिए गए थे, पानी के मीटर लगाए गए थे। लोग बाकायदा सरकारी विभागों को इसका भुगतान कर रहे थे। जब उन घरों से टैक्स और बिल वसूलना वैध था, तो अचानक वह पूरा आशियाना पूरी तरह अवैध कैसे हो गया? यह दोगलापन नहीं तो और क्या है? यह घटना सीधे तौर पर हमारी व्यवस्था के उस दोहरे चरित्र को उजागर करती है जो रसूखदारों, अमीरों के अवैध फार्महाउसों, और बड़े-बड़े कमर्शियल मॉल के अवैध निमार्णों पर सालों-साल अदालती स्टे की आड़ में आंखें मूंदे रहती है। लेकिन जब किसी सड़क चौड़ीकरण या सौंदर्यीकरण की बात आती है, तो कानून का सबसे पहला और सबसे बेरहम बुलडोजर समाज के सबसे कमजोर और गरीब तबके की बस्तियों पर ही आकर गिरता है।

प्रयास करेगी कि इन गरीबों को 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' नीति या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत जल्द से जल्द पक्की छत मुहैया कराई जा सके। विकास जनता की सहूलियत के लिए होता है, उन्हें बेघर करने के लिए नहीं। बुलडोजर की कार्रवाई खत्म होने के बाद शालीमार बाग के उस हिस्से की तस्वीरें किसी युद्ध क्षेत्र जैसी नजर आती हैं। चारों तरफ बिखरा हुआ कंक्रीट, टूटी हुई दीवारें और ढहे हुए पिलर। कहीं किसी मासूम बच्चे की स्कूल की आधी फटी हुई किताबें और कॉपियां मलबे में दबी सिसक रही हैं, तो कहीं किसी लाचार मां का आधा जला हुआ चूल्हा और बिखरे हुए बर्तन अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि दिल्ली में मानसून की दस्तक होने वाली है। ऐसे भीषण मौसम में, जब आसमान से आग बरस रही हो या मूसलाधार बारिश होने वाली हो, इन 150 से अधिक परिवारों के पास सिर छुपाने की कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। वे अपने घरों से बचाए गए थोड़े-बहुत सामान को तिरपाल से ढककर सड़कों के किनारे बैठने को मजबूर हैं। राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, बयानों के दौर आते-जाते रहेंगे, लेकिन जो घाव इन परिवारों के दिलों पर लगे हैं, उनकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी।

विकास की अंधी दौड़

शालीमार बाग की यह दर्दनाक कहानी सिर्फ दिल्ली के एक वीरान कोने की नहीं है। आज

शालीमार बाग की घटना अत्यंत हृदयविदारक है। दिल्ली के विकास और मास्टर प्लान के लिए सड़कों का चौड़ीकरण प्रशासनिक रूप से अनिवार्य हो सकता है, लेकिन विकास की कोई भी परियोजना गरीबों की चीखों पर खड़ी नहीं होनी चाहिए। कानून की आड़ में मानवीय संवेदनाओं को बेरहमी से कुचला नहीं जा सकता। हमारी सरकार इन बेघर हुए परिवारों को जल्द से जल्द पक्की छत व पुनर्वास मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री

देश के अलग-अलग राज्यों और कोनों से 'बुलडोजर जस्टिस' या 'बुलडोजर गवर्नेंस' की खबरें हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अवैध निमार्णों को हटाना प्रशासनिक और कानूनी नजरिए से पूरी तरह सही और तार्किक हो सकता है, लेकिन न्याय का एक बुनियादी और सर्वमान्य सिद्धांत यह भी कहता है कि किसी भी नागरिक को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के सीधे सड़क पर नहीं फेंका जा सकता। जब तक हमारी आधुनिक विकास की अवधारणा में समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता, करुणा और पुनर्वास की इच्छाशक्ति नहीं होगी, तब तक ऐसी हर चौड़ी और चमचमाती सड़क के नीचे किसी न किसी गरीब का आशियाना, उसकी उम्मीदें और उसका भविष्य इसी तरह दफन होता रहेगा। शालीमार बाग के मलबे से उठती हुई धूल आज दिल्ली के नीति-नियंताओं, योजनाकारों और पूरी न्याय प्रणाली से चीख-चीखकर यह यक्ष प्रश्न पूछ रही है, क्या बिना किसी पुनर्वास के, बिना किसी छत के, इंसानों को इस तरह सड़कों पर उजाड़ देना ही एक सभ्य समाज का असली 'न्याय' है?

निर्माणाधीन

श्री सीताराम गौ आश्रम एवं सम्मान सदन

एन.एच–2 अझई वृन्दावन मथुरा यू.पी.

वर्तमान में 52 एकड़ परिसर में

- 500 गौमाता का आश्रम निर्माण
- 50 वेड का भक्तो के लिए सम्मान सदन
- 500 गज का सतसंग भवन
- 2 कुटिया महाराज जी के लिए
- 50 वेड का हास्पिटल प्रारम्भ करने का लक्ष्य
- संस्कृति पाठशाला का निर्माण

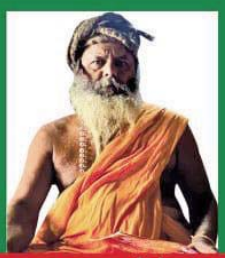

सन्त राम भरोसे दास जी महाराज

केवल 11 हजार में आजीवन ट्रस्टी

ट्रस्टी बनने के लिए सम्पर्क करे 9911662767, 8287499312

कॉरपोरेट ऑफिसः 298/299, ब्लॉक इ- 9, सेक्टर 5, नई दिल्ली-110086

Email:-shrisamadhanfoundation@gmail.com

Samadhan Foundation

IFFCO

पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत-किसान बने खुशहाल

नैनो यूरिया प्लस • नैनो डीएपी • नैनो एनपीके
नैनो ज़िंक • नैनो कॉपर • धरामृत • सागरिका • जैव उर्वरक

उत्तम खेती के लिए स्मार्ट समाधान

- मिट्टी की उर्वरता बढ़े
- पर्यावरण के लिए सुरक्षित
- कम मात्रा में अधिक प्रभाव

इफको का है यह अभियान स्वस्थ हो धरती, खुशहाल बने किसान

- कम लागत में अधिक उत्पादन
- फसल की गुणवत्ता में सुधार
- भंडारण एवं प्रयोग करने में आसान

नैनो उर्वरक अपनाओ, फसलों का उत्पादन, गुणवत्ता और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाओ।

इफको के नैनो उर्वरक सम्पूर्ण स्वदेशी हैं | इफको द्वारा विकसित नैनो उर्वरक, आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर कृषि की पहचान हैं

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली - 110017
दूरभाष: 91-11-26510001, 91-11-42592626 | **वेबसाइट:** www.iffco.in
ग्राहक सेवा हेल्पलाइन नंबर (टोल फ्री): 1800 103 1967

इफको के उत्पाद और सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें और हमसे जुड़ें

इफको का किसानों और कर्मचारियों को तोहफा

@ प्रमोद तिवारी

भारत के सहकारी आंदोलन को एक नई और प्रगतिशील दिशा देते हुए दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्थाओं में शुमार इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने अपनी 55वीं वार्षिक आम बैठक में कई युगांतकारी फैसले लिए हैं। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित मंच पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में देश के कोने-कोने से आए 850 से अधिक सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, प्रगतिशील किसान नेताओं और सम्मानित सदस्यों की गरिमामयी मौजूदगी रही। इस महामंथन में इफको ने न सिर्फ अपने बंपर मुनाफे के रिकॉर्ड आंकड़े साझा कर कॉरपोरेट जगत को चौंकाया, बल्कि देश के अन्नदाताओं, ग्रामीण महिलाओं और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अपना खजाना पूरी तरह खोल दिया। यह वार्षिक बैठक भारतीय सहकारिता के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है, क्योंकि इसमें देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, उनकी निर्णय क्षमता और उनके अद्वितीय नेतृत्व को एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक पहचान दी गई है।

महिला सहकारिता नेताओं को मिले शीर्ष पुरस्कार: इफको के पांच दशकों से अधिक लंबे और गौरवशाली इतिहास में यह पहला ऐसा ऐतिहासिक मौका था, जब संस्था के दोनों सबसे प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार देश की महिला सहकारी नेताओं के नाम रहे। इस ऐतिहासिक निर्णय को रेखांकित करते हुए इफको के चेयरमैन दिलीप संघानी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर यह समय बेहद खास है, क्योंकि वर्ष 2026 को 'अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे पावन व महत्वपूर्ण समय में देश की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर संभालने वाली मातृशक्ति को सम्मानित करना इफको परिवार के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण व भावुक क्षण है। इस बार पुरस्कारों की फेहरिस्त में भौगोलिक व सांस्कृतिक विविधता की एक बेहद खूबसूरत झलक देखने को मिली, जब देश के दो अलग-अलग छोरों से आईं महिलाओं को उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया:

इफको सहकारिता रत्न पुरस्कार: आतंकवाद और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दंश को झेलने वाले जम्मू-कश्मीर की शकीला अख्तर को इस वर्ष के सर्वोच्च 'सहकारिता रत्न पुरस्कार' से नवाजा गया। शकीला अख्तर ने घाटी की रूढ़िवादिता और सामाजिक बंधनों को तोड़कर ग्रामीण महिलाओं को कृषि, बागवानी और सहकारी आंदोलन से जोड़ा है। उन्होंने जमीनी स्तर पर महिलाओं को संगठित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और महिला सशक्तिकरण की एक नई इबारत लिखने का जो साहसिक कार्य किया है, उसी के सम्मान स्वरूप उन्हें 11 लाख की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया।

इफको सहकारिता बंधु पुरस्कार: दूसरी ओर, देश के पश्चिमी छोर यानी गुजरात की धरती से ताल्लुक रखने वाली भावना गोंडलिया को 'इफको सहकारिता बंधु पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। भावना गोंडलिया ने सहकारी गतिविधियों में महिलाओं की पैठ को बेहद मजबूत किया है। उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों, डेयरी उद्योग और स्थानीय बचत समूहों के माध्यम से हजारों ग्रामीण महिलाओं को सीधे तौर पर आजीविका से जोड़कर एक रोल मॉडल स्थापित किया है। उन्हें भी सम्मान के तौर पर ₹11 लाख की नकद राशि और

स्मृति चिह्न प्रदान किया गया।

कर्मचारियों को सबसे बड़ा इंसेंटिव

आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो इफको ने वैश्विक मंदी और बदलती बाजार परिस्थितियों के बावजूद अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति और कुशल प्रबंधन का लोहा मनवाया है। संस्था ने इस वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए ₹4,585 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया है। एक सहकारी संस्था होने के नाते, इस बंपर मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा संस्था ने अपने उन हितधारकों और कर्मचारियों के कल्याण में लगाने का फैसला किया, जिन्हें इस पूरी व्यवस्था की असली रीढ़ और ताकत माना जाता है। इफको के प्रबंध निदेशक के. जे. पटेल ने बैठक में वित्तीय लेखा-जोखा पेश करते हुए एक ऐसी घोषणा की, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कर्मचारियों के लिए ₹490.65 करोड़ का इंसेंटिव (कर्मचारी प्रोत्साहन) जारी किया जा रहा है।

यह वित्तीय प्रोत्साहन इफको के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक आंकड़ा है। इफको का यह कल्याणकारी दृष्टिकोण यहीं नहीं रुका; सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए प्रबंधन ने निचले स्तर के संविदा और दैनिक कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा मानवीय कदम उठाया। संस्था ने अपने निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन की सीमा को बढ़ाकर सीधे ₹20,000 प्रति माह तय करने की ऐतिहासिक घोषणा की। इस न्यूनतम वेतन वृद्धि के फैसले को सुचारू रूप से लागू करने के लिए इफको ने अपने बजट से ₹140 करोड़ का एक अलग और अतिरिक्त फंड आवंटित किया है, ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सम्मानजनक जीवन मिल सके।

नए क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता का रोडमैप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन 'सहकार से समृद्धि' को धरातल पर उतारने के लिए इफको अब पारंपरिक और पुरानी खेती के ढर्रे से आगे बढ़कर अत्याधुनिक कृषि तकनीकों की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस 55वीं एजीएम में सतत कृषि के प्रति अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नैनो फर्टिलाइजर (जैसे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी) के उपयोग को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि नैनो तकनीकों के आने से न केवल छोटे और सीमांत किसानों की खेती की लागत आधी हो जाएगी, बल्कि जमीन की उर्वरा शक्ति भी बची रहेगी और किसानों की शुद्ध आय में भारी इजाफा होगा। इसके साथ ही, इस महाधिवेशन में इफको के अन्य सहयोगी उपक्रमों और नए व्यावसायिक क्षेत्रों के विस्तार का एक विस्तृत ब्लूप्रिंट भी पेश किया गया। इसमें उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के लिए 'भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड', किसानों के उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए 'नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड', ग्रामीण आंचल में सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए 'इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस', किसानों को एक ही छत के नीचे कृषि इनपुट देने वाला 'इफको बाजार', ग्रामीण ऋण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 'किसान रूरल फाइनेंस' और परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने वाली 'भारत टैक्सी' जैसी पहलों के रणनीतिक विस्तार का खाका खींचा गया।

सहकारिता आंदोलन के सशक्त सारथी दिलीप संघानी

इफको को आधुनिक, पारदर्शी और पूरी तरह किसान-हितैषी ऊंचाइयों पर ले जाने के पीछे इसके चेयरमैन दिलीप संघानी का दूरदर्शी और जमीनी नेतृत्व काम कर रहा है। गुजरात के अमरेली जिले के एक साधारण किसान परिवार से आने वाले दिलीप संघानी आज भारत के सहकारिता क्षेत्र के सबसे कद्दावर, अनुभवी और सम्मानित चेहरों में से एक हैं।

राजनीतिक व प्रशासनिक अनुभवः दिलीप संघानी का सार्वजनिक जीवन चार दशकों से भी अधिक लंबा है। वे गुजरात सरकार में कृषि, सहकारिता, कानून, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी प्रशासनिक कुशलता साबित कर चुके हैं। इसके अलावा वे भारतीय संसद के सदस्य (लोकसभा सांसद) और गुजरात विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में भी लंबे समय तक विधायी कार्यों का नेतृत्व कर चुके हैं।

सहकारी तंत्र के मार्गदर्शकः सहकारिता के प्रति उनके समर्पण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे देश में सहकारिता की शीर्ष संस्था 'राष्ट्रीय सहकारी संघ' के अध्यक्ष और 'गुजरात राज्य सहकारी बैंक' के चेयरमैन जैसी प्रतिष्ठित भूमिकाएं निभा चुके हैं। वर्ष 2021 में सर्वसम्मति से इफको का चेयरमैन चुने जाने के बाद से उन्होंने देश के करोड़ों किसानों तक डिजिटल तकनीकों को पहुंचाने, उर्वरक वितरण प्रणाली को बिचौलियों से मुक्त करने और सहकारी तंत्र को पूरी तरह पारदर्शी बनाने में अद्वितीय सफलता हासिल की है। उन्हीं के कुशल मार्गदर्शन में इफको ने दुनिया की पहली 'नैनो यूरिया' तकनीक को न केवल ईजाद किया, बल्कि उसे वैश्विक पटल पर भारत की वैज्ञानिक क्षमता के प्रतीक के रूप में स्थापित भी किया।

बदलते ग्रामीण भारत का नया घोषणापत्रः कुल मिलाकर देखा जाए तो इफको की 55वीं वार्षिक आम बैठक महज एक औपचारिक या सालाना कॉरपोरेट बैठक नहीं थी, बल्कि यह बदलते ग्रामीण भारत का एक नया और सशक्त घोषणापत्र बनकर सामने आई है। इस बैठक ने देश के नीति-नियंताओं और उद्योग जगत को यह कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि सहकारिता के मूल सिद्धांतों को सही नीयत, मानवीय दृष्टिकोण और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के साथ जोड़ दिया जाए, तो यह मॉडल न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकता है, बल्कि देश की आधी आबादी (महिला शक्ति) और समाज के सबसे अंतिम पायदान पर पसीना बहाने वाले कर्मचारियों को भी उनका वास्तविक हक और सम्मान दिला सकता है। सहकारिता का यह 'इफको मॉडल' आज के दौर में नए भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभर रहा है।

'कॉकरोच जनता पार्टी' के उभार के मायने

@ अशांशु संचेती

भारतीय राजनीति में सोशल मीडिया और मीम्स अब केवल मनोरंजन या समय काटने का साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि वे व्यवस्था के खिलाफ पनप रहे एक बहुत बड़े और गहरे असंतोष को व्यक्त करने का सबसे धारदार हथियार बन चुके हैं। हाल के दिनों में इंटरनेट की दुनिया में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) नाम का एक बेहद अजीबो गरीब और अभूतपूर्व डिजिटल आंदोलन तेजी से उभरा है, जिसने मुख्यधारा के राजनीतिक पंडितों और समाज शास्त्रियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, विशेषकर इंस्टाग्राम,एक्स और फेसबुक पर इस तथाकथित आभासी पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या रातों-रात लाखों से होती हुई करोड़ों में पहुंच चुकी है। देश का युवा वर्ग, जो अक्सर अलग-अलग वैचारिक, धार्मिक और क्षेत्रीय दायरों में बिखरा रहता है, इस समय पहली बार एक सुर में इस आत्म-निंदा से भरे 'कॉकरोच' ब्रांडिंग के पीछे एकजुट खड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस डिजिटल सुनामी के बीच कई गंभीर सवाल भी तैर रहे हैं। सवाल यह है कि इस पूरी मुहिम के पीछे असल में कौन लोग हैं, इनका वास्तविक एजेंडा क्या है, और क्या भारतीय जनता का यह तीखा गुस्सा किसी वास्तविक राजनीतिक या सामाजिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है, या फिर यह भी इतिहास के अन्य आंदोलनों की तरह केवल एक और चुनावी 'वोट-काटू' प्रोपेगैंडा बनकर रह जाएगा? इस पार्टी के बारे में कोई भी अंतिम धारणा बनाना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि डिजिटल दुनिया की हवा जितनी तेजी से चलती है, उतनी ही तेजी से बदल भी जाती है।

इस पूरे विवाद, गुस्से और आंदोलन की जड़ें सीधे तौर पर देश की सर्वोच्च अदालत की एक तल्ख टिप्पणी से जुड़ी हुई हैं। हाल ही में एक संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश(सीजेआई) सूर्यकांत ने कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं, सोशल मीडिया पर सक्रिय एक्टिविस्टों और बार-बार आरटीआई लगाने वाले कार्यकताओं के संदर्भ में 'कॉकरोच' (तिलचट्टा) और 'परजीवी' जैसे बेहद कड़े और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि, जब इस टिप्पणी को लेकर चौतरफा आलोचना शुरू हुई और सोशल मीडिया पर गुस्सा उबलने लगा, तो सुप्रीम कोर्ट और स्वयं सीजेआई की ओर से एक स्पष्टीकरण भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि उनके बयान को संदर्भ से बाहर जाकर तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था और वे दरअसल केवल 'फर्जी डिग्री' धारकों और ब्लैकमेलिंग करने वाले तत्वों की बात कर रहे थे। लेकिन राजनीति और जनभावनाओं की दुनिया में तब तक तीर कमान से छूट चुका था और जो संदेश जनता तक जाना था, वह जा चुका था। देश के पढ़े-लिखे लेकिन बेरोजगार युवाओं, अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक्टिविस्टों और आम नागरिकों को यह भाषा सीधे अपने आत्मसम्मान पर चोट जैसी लगी। युवाओं को लगा कि एक लोकतांत्रिक देश में, जहां उन्हें राष्ट्र निमार्ता कहा जाना चाहिए, वहां देश की सबसे बड़ी अदालत उन्हें 'परजीवी' कह रही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया रणनीतिकार अभिजीत दिपके ने युवाओं के इसी सुलगते हुए गुस्से को भांप लिया और इसे एक संगठित डिजिटल अभियान में बदलते हुए 'कॉकरोच जनता पार्टी' की नींव रख दी। इस आंदोलन ने बहुत ही चतुराई से व्यवस्था के दिए जख्म को ही अपना तमगा बना लिया और इसका नारा रखा गया कि 'उन्होंने हमें कुचलने की कोशिश की, लेकिन हम फिर वापस आ गए।' इस तथाकथित डिजिटल पार्टी की सदस्यता के नियम और शर्तें भी इतनी व्यंग्यात्मक और तंजभरी रखी गई हैं कि वे सीधे युवाओं को आकर्षित कर रही हैं, जैसे कि सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का बेरोजगार होना, व्यवस्था से निराश होना, चौबीसों घंटे ऑनलाइन रहना और पेशेवर तरीके से मीम्स के जरिए सत्ता पर अपनी भड़ास निकालने की क्षमता रखना आवश्यक है।

इस आंदोलन की इस अभूतपूर्व और अकल्पनीय हाइप को देखकर कई वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और आम नागरिक इसकी तुलना वर्ष 2011-12 के ऐतिहासिक 'अन्ना हजारे आंदोलन' से कर रहे हैं, जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी थी। लेकिन वह पुराना अनुभव देश की आम जनता के लिए सुखद नहीं रहा। उस समय देश ने देखा था कि कैसे विदेशी फंडिंग, कॉर्पोरेट घरानों की बैंकिंग और मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से के प्रायोजित समर्थन से घिरे एक आंदोलन ने तत्कालीन

मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने बड़े और सनसनीखेज आरोप लगाए कि पूरी सरकार ही कटघरे में खड़ी हो गई। उस आंदोलन का नतीजा क्या निकला? परिणाम यह हुआ कि जिस जनलोकपाल बिल के लिए पूरा देश सड़कों पर उतर आया था, वह आज तक अपने असली स्वरूप में नहीं आ सका। अन्ना हजारे खुद आंदोलन खत्म होने के बाद परिदृश्य से पूरी तरह गायब हो गए या उन्हें गायब कर दिया गया। लेकिन उस आंदोलन की लहर पर सवार होकर देश में एक ऐसी नई राजनीतिक सत्ता का उदय जरूर हो गया, जिसने पूरे देश का राजनीतिक ताना-बाना ही बदलकर रख दिया। इसके बाद जब मामले देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, तो टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला और कोयला घोटाला जैसी बड़ी-बड़ी जांच समितियां और आरोप पूरी तरह से निराधार और खोखले साबित हुए। पिछले 12-13 सालों की कानूनी लड़ाइयों में उस समय लगाए गए आरोपों में से एक भी बड़ा आरोप अदालतों में साबित नहीं हो सका। विडंबना की पराकाष्ठा यह है कि आज देश में भ्रष्टाचार खत्म होने के बजाय एक नए और विकृत रूप में सामने आया है, जिसे अब लोग 'जीवन का शिष्टाचार' कहने लगे हैं। आज स्थिति यह है कि हजारों करोड़ रुपये के घोटाले या घपले देश की जनता के लिए सिर्फ मजाक बनकर रह गए हैं और भ्रष्टाचार एक सामान्य सी दैनिक घटना लगने लगी है।

उस अन्ना आंदोलन ने असल में देश की जनता का 'आंदोलनों' व 'क्रांतियों' के प्रति जो एक पवित्र विश्वास था, उसे हमेशा के लिए तोड़ दिया। यही सबसे बड़ी वजह है कि आज भारतीय जनता कॉकरोच जनता पार्टी के इस नए उभार को देखकर भी तुरंत किसी धारणा को बनाने या इस पर भरोसा करने से हिचकिचा रही है।

इसके साथ ही, देश के मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए इस आंदोलन के पीछे एक और गहरी राजनीतिक साजिश या प्रोपेगैंडा होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक गलियारों में यह गंभीर चर्चा भी चल रही है कि कहीं यह 'कॉकरोच जनता पार्टी' खुद सत्ताधारी दल भाजपा द्वारा ही पर्दे के पीछे से प्रायोजित किया गया कोई प्रयोग तो नहीं है? इतिहास गवाह है कि जब भी कोई गैर-पारंपरिक व लीक से हटकर काम करने वाली पार्टी, जैसे कि पूर्व में आम आदमी पार्टी या कई अन्य क्षेत्रीय दल, अचानक राष्ट्रीय स्तर पर उभरते हैं, तो वे अंततः देश के जागरूक और असंतुष्ट मतदाताओं के वोटों को बांटने का काम करते हैं। यदि यह कॉकरोच आंदोलन कल को सिर्फ सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलकर एक वास्तविक राजनीतिक दल का रूप लेता है और देश के आगामी चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े करता है, तो यह तय है कि इससे जो भी वोट कटेंगे, वे मौजूदा सरकार से नाराज लोगों के यानी एंटी-इंकंबेंसी (सत्ता विरोधी) वोट होंगे। विपक्ष के वोटों का यह बिखराव सीधे तौर पर मौजूदा सत्ताधारी सरकार को ही राजनीतिक रूप से अजेय बना देगा। यही कारण है कि देश का समझदार व गंभीर नागरिक वर्ग इस पार्टी की लोकप्रियता को कौतुक से देख तो रहा है, लेकिन इसे किसी भी तरह से सीधे तौर पर एंडोर्स या समर्थित करने से पूरी तरह बच रहा है।

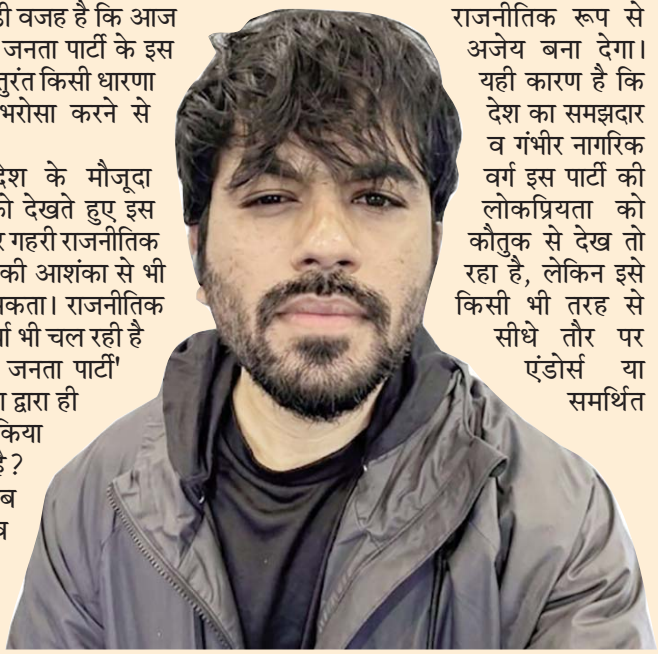

अंततः कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। क्या यह डिजिटल दुनिया का महज ऐसा बुलबुला है जो कुछ दिनों के शोर-शराबे के बाद फूट जाएगा, या फिर यह जमीनी स्तर पर जाकर देश के करोड़ों युवाओं के रोजगार, लगातार हो रहे पेपर लीक, नीट परीक्षा जैसे बड़े विवादों और देश में बढ़ती आर्थिक असमानता के खिलाफ एक वास्तविक वैचारिक क्रांति का रूप अख्तियार करेगी? भले ही इस आंदोलन को शुरू करने वाले लोगों की मंशा कितनी भी पवित्र हो या फिर उनका गुप्त उद्देश्य केवल विधानसभा या संसद तक पहुंचने का रास्ता तलाशना हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात पूरी तरह से साफ कर दी है कि भारतीय जनता, और विशेषकर देश का युवा वर्ग, इस समय व्यवस्था की घोर अनदेखी, आर्थिक तंगी और शीर्ष स्तर से आने वाली अपमानजनक टिप्पणियों से भीतर तक बेहद उद्वेलित और परेशान है। देश के मुख्य न्यायाधीश की उस एक टिप्पणी पर सत्ताधारी दल की रहस्यमयी खामोशी भी युवाओं को बहुत ज्यादा चुभ रही है, जो यह संकेत देती है कि शायद सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के विचार भी देश के युवाओं और एक्टिविस्टों के प्रति बहुत सकारात्मक नहीं हैं। सरकार और विपक्ष दोनों के लिए इस समय बुद्धिमानी इसी में होगी कि वे इस 'कॉकरोच आंदोलन' को केवल एक इंटरनेट मीम या सोशल मीडिया की बकवास समझकर कम आंकने की भूल कतई न करें, क्योंकि जनता की इस मूक लेकिन उग्र प्रतिक्रिया के पीछे एक बहुत बड़ा लावा सुलग रहा है।

परीक्षा नहीं, भविष्य लीक हुआ है

@ अजीत सिंह

भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं अब केवल करियर का माध्यम नहीं रह गई हैं; वे करोड़ों परिवारों की आकांक्षाओं, सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक भविष्य का केंद्र बन चुकी हैं। यही कारण है कि जब राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 को कथित पेपर लीक और 'क्वेश्चन बैंक' विवाद के बाद रद्द किया गया, तो यह केवल एक परीक्षा का स्थगन नहीं था। यह उस भरोसे पर आघात था, जिसके आधार पर लाखों छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं और परिवार अपनी जमा-पूंजी दांव पर लगाते हैं। देशभर से लगभग 24 लाख छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। मेडिकल शिक्षा की सीमित सीटों और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के बीच यह परीक्षा देश की सबसे कठिन और निर्णायक परीक्षाओं में मानी जाती है। लेकिन परीक्षा के कुछ ही दिनों बाद राजस्थान, उत्तराखंड और अन्य राज्यों से सामने आई रिपोर्टों ने पूरे तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया। जांच एजेंसियों के अनुसार परीक्षा से पहले एक कथित 'क्वेश्चन बैंक' छात्रों तक पहुंचा, जिसमें मौजूद बड़ी संख्या में प्रश्न वास्तविक परीक्षा से मेल खाते पाए गए।

राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह की जांच में सामने आया कि सीकर, जयपुर और झुंझुनूं जैसे कोचिंग केंद्रों में परीक्षा से पहले प्रश्न सामग्री प्रसारित हुई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह सामग्री व्हाट्सऐप और अन्य एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई छात्रों तक पहुंची। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि कथित प्रश्न बैंक में 300 से अधिक प्रश्न थे, जिनमें से लगभग 150 प्रश्न हूबहू परीक्षा में दिखाई दिए। यदि यह तथ्य पूरी तरह सिद्ध होता है, तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि संगठित परीक्षा अपराध की श्रेणी में आता है। इस पूरे प्रकरण का सबसे चिंताजनक पक्ष यह नहीं कि पेपर लीक हुआ या नहीं; बल्कि यह है कि अब छात्रों और अभिभावकों का एक बड़ा वर्ग यह मानने लगा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल मेहनत पर्याप्त नहीं रह गई। यही भावना किसी भी लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा संकट है।

भारत में मेडिकल सीटों की स्थिति अत्यंत असंतुलित है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में एमबीबीएस की कुल सीटें लगभग 1.20 लाख के आसपास हैं, जबकि परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 24 लाख तक पहुंच चुकी है। इसका सीधा अर्थ है कि हर 20 छात्रों में केवल 1 छात्र को मेडिकल सीट मिल पाती है। यह अनुपात न केवल प्रतियोगिता को असामान्य रूप से कठोर बनाता है, बल्कि मानसिक दबाव को भी कई गुना बढ़ा देता है। कोटा, सीकर, पटना, दिल्ली और हैदराबाद जैसे कोचिंग केंद्र अब केवल शिक्षा के स्थल नहीं, बल्कि एक समानांतर परीक्षा अर्थव्यवस्था में बदल चुके हैं। एक छात्र की वार्षिक तैयारी लागत औसतन 2 लाख से 5 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। इसमें कोचिंग फीस, हॉस्टल, भोजन, टेस्ट सीरीज, किताबें और डिजिटल सब्सक्रिप्शन शामिल हैं। लाखों परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा इस उम्मीद में निवेश करते हैं कि परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष होगी। लेकिन जब परीक्षा रद्द होती है, तब केवल परीक्षा केंद्र नहीं टूटता – पूरा पारिवारिक संतुलन हिल जाता है।

कई छात्रों ने सोशल मीडिया मंचों पर लिखा कि वे दोबारा उसी मानसिक स्थिति में तैयारी नहीं कर पाएंगे। कुछ ने वर्षों की मेहनत को 'अनिश्चित व्यवस्था का शिकार' बताया। यह प्रतिक्रिया केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक थकान का संकेत है जो आज के प्रतियोगी युवा समाज की वास्तविकता बन चुकी है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आज का युवा केवल परीक्षा नहीं दे रहा, बल्कि वह लगातार तुलना, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक दबाव के बीच जी रहा है। एक ओर परिवार की उम्मीदें हैं, दूसरी ओर लगातार बढ़ती फीस, सीमित अवसर और अस्थिर रोजगार बाजार। ऐसे समय में यदि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगें, तो उसका प्रभाव केवल रिजल्ट तक सीमित नहीं रहता; वह युवाओं के आत्मविश्वास और सामाजिक भरोसे को भी प्रभावित करता है।

नीट विवाद कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कभी तकनीकी गड़बड़ी, कभी सर्वर फेल, कभी पेपर लीक और कभी मूल्यांकन विवाद-इन घटनाओं ने परीक्षा एजेंसियों की विश्वसनीयता को कमजोर किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि देश में एक पारदर्शी, आधुनिक और तकनीकी रूप से सुरक्षित परीक्षा प्रणाली विकसित हो सके। लेकिन आज वही संस्था लगातार विवादों के केंद्र में दिखाई दे रही है। यह केवल प्रशासनिक चुनौती नहीं, बल्कि संस्थागत जवाबदेही का प्रश्न है। परीक्षा प्रणाली केवल तकनीक से सुरक्षित नहीं होती। किसी भी परीक्षा की विश्वसनीयता पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई पर आधारित होती है। यदि इन तीनों में कमी आए, तो तकनीकी सुरक्षा भी पर्याप्त नहीं रह जाती।

नीट 2026 विवाद ने यह भी स्पष्ट किया कि डिजिटल युग में परीक्षा अपराधों का स्वरूप बदल चुका है। पहले प्रश्नपत्र फोटोकॉपी और कागजों के माध्यम से लीक होते थे; अब एन्क्रिप्टेड ऐप, निजी चैनल, क्लाउड शेयरिंग और 'फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स' जैसे डिजिटल संकेत पूरे नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। यानी परीक्षा सुरक्षा अब केवल परीक्षा केंद्र तक सीमित नहीं रह सकती। इस पूरे विवाद की सबसे गहरी परत सामाजिक असमानता से जुड़ी हुई है। भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं लंबे समय तक सामाजिक गतिशीलता का माध्यम रही हैं। गांवों और छोटे शहरों के लाखों छात्रों के लिए यह अवसर था कि वे सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन की दिशा बदल सकें। जब परीक्षा प्रक्रिया पर संदेह बढ़ने लगे, तब यह विश्वास कमजोर होता है कि 'मेहनत से सफलता संभव है।'

एक ओर वे छात्र हैं जो लाइब्रेरी, किराये के कमरों और सीमित संसाधनों के बीच तैयारी करते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे नेटवर्क दिखाई देते हैं जिनके पास तकनीकी पहुंच, प्रभाव और गोपनीय सूचना पहले से उपलब्ध रहती है। यही वह बिंदु है जहां प्रतियोगिता धीरे-धीरे समान अवसर से हटकर 'संपर्क आधारित लाभ' में बदलने लगती है। यदि यह धारणा युवाओं के मन में स्थायी रूप से बैठ जाती है, तो उसका प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास को भी कमजोर करेगा। परीक्षा रद्द होने का आर्थिक प्रभाव भी अत्यंत गंभीर है। लाखों छात्रों को पुनः यात्रा, आवास, अध्ययन सामग्री और मानसिक तैयारी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिन परिवारों ने पहले ही भारी खर्च किया है, उनके लिए यह दोहरी मार जैसी स्थिति है। यदि औसतन प्रत्येक छात्र की तैयारी और परीक्षा से संबंधित लागत 3 लाख रुपये मानी जाए, तो 24 लाख छात्रों पर यह राशि लगभग 72 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचती है। यह केवल एक अनुमानित गणना है, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि प्रतियोगी परीक्षाएं आज एक विशाल आर्थिक ढांचे में बदल चुकी हैं।

भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, लेकिन यही युवा वर्ग आज सबसे अधिक असुरक्षित और बेचैन दिखाई देता है। रोजगार की सीमित संभावनाएं, बढ़ती प्रतियोगिता, परीक्षा विवाद और आर्थिक दबाव -ये सभी मिलकर एक गहरी सामाजिक अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। युवाओं की नाराजगी केवल किसी एक परीक्षा को लेकर नहीं है; यह उस भावना से जुड़ी है कि व्यवस्था उनकी मेहनत के अनुरूप भरोसेमंद नहीं रह गई। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर केवल विरोध नहीं, बल्कि व्यंग्य, निराशा और अविश्वास का स्वर भी तेज होता जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अत्यंत गंभीर संकेत माना जाता है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की स्थिरता केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि उसकी युवा पीढ़ी के भरोसे से तय होती है। सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी है पुनर्परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन प्रश्न केवल दोषियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। आवश्यकता उस व्यापक ढांचे की समीक्षा की है जिसमें देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। यह समय केवल तकनीकी सुधारों का नहीं, बल्कि संस्थागत पुनर्विश्वास का है। परीक्षा प्रणाली को इस स्तर तक पारदर्शी बनाना होगा कि छात्रों को यह महसूस हो सके कि उनका भविष्य किसी 'नेटवर्क' या 'लीक' से नहीं, उनकी मेहनत से तय होगा। नीट 2026 विवाद ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की सबसे बड़ी चुनौती केवल रोजगार या शिक्षा नहीं, बल्कि भरोसे की पुनर्स्थापना है।

बंगाल की हिंसा लोकतंत्र पर धब्बा

@ राष्ट्र समाज

पश्चिम बंगाल में हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनावों के बाद जिस प्रकार हिंसा, हत्याओं, आगजनी और राजनीतिक प्रतिशोध की घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने केवल राज्य की शांति को ही नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को भी आहत किया है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव माना जाता है, किंतु जब यह उत्सव हिंसा, भय और प्रतिशोध में बदल जाए तो यह केवल राजनीतिक असफलता नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक पतन का संकेत बन जाता है। बंगाल की ताजा हिंसक घटनाएं इसी चिंता को सामने लाती हैं। चुनाव के दौरान छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ था। लेकिन परिणामों की घोषणा के बाद जिस प्रकार राजनीतिक दलों के समर्थक एक-दूसरे के खिलाफ आक्रामक हुए, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब वैचारिक संघर्ष न रहकर प्रतिशोध और वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकताओं के बीच हिंसक झड़पें, कई लोगों की हत्याएं और विशेष रूप से सुवेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पूरे घटनाक्रम को और अधिक गंभीर बना दिया। आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह क्यों बची रहनी चाहिए?

यह विडंबना है कि भारत, जिसने विश्व को अहिंसा, करुणा और 'वसुधैव कुटुम्बकम' का मंत्र दिया, आज वही देश राजनीतिक हिंसा के कारण अपनी छवि धूमिल करता दिखाई देता है। महात्मा गांधी ने राजनीति को नैतिकता और सेवा से जोड़ा था, लेकिन आज राजनीति सत्ता, प्रतिशोध और भय का माध्यम बनती जा रही है। बंगाल की हिंसा इस बीमारी का एक भयावह उदाहरण है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास हिंसा से अछूता नहीं रहा है। वामपंथी शासन के लंबे दौर से लेकर तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल तक राजनीतिक संघर्ष कई बार रक्तरंजित रूप में सामने आया। बूथ कब्जाने, विरोधियों को डराने, स्थानीय दबंगों और अपराधी तत्वों का राजनीतिक संरक्षण-ये सब बंगाल की राजनीति की कटु वास्तविकताएं रही हैं। सत्ता बदलती रही, लेकिन राजनीतिक संस्कृति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आ सका। यही कारण है कि चुनाव परिणामों के बाद भी हिंसा का वातावरण बनता है और आम नागरिक भय तथा असुरक्षा के बीच जीने को मजबूर होता है।

दरअसल जब राजनीति विचार व जनसेवा से हटकर केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम बन जाती है, तब हिंसा उसका स्वाभाविक परिणाम बनती है। हार को लोकतांत्रिक विनम्रता से स्वीकार करने के बजाय प्रतिशोध का माध्यम बना लेना लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। यही कारण है कि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देशों और विजय जुलूसों पर प्रतिबंध के बावजूद हिंसक घटनाएं हुईं। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की नैतिक विफलता भी है। ममता बनर्जी द्वारा चुनाव परिणामों पर सवाल उठाना और राजनीतिक टकराव को तीखा बनाना हो या भाजपा द्वारा आक्रामक राजनीतिक प्रतिक्रिया-दोनों पक्षों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता

दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वे जनता को शांति और संयम का संदेश दें। दुर्भाग्य से हमारे राजनीतिक दल अक्सर कार्यकताओं की भावनाओं को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें उकसाने का काम करते हैं। परिणाम स्वरूप हिंसा सामान्य राजनीतिक व्यवहार का हिस्सा बनती जा रही है।

सबसे अधिक पीड़ा इस बात की है कि राजनीतिक हिंसा की कीमत हमेशा आम जनता को चुकानी पड़ती है। जिन लोगों के घर जलते हैं, जिन परिवारों के सदस्य मारे जाते हैं, जिन छोटे व्यापारियों की दुकानें टूटती हैं, उनका राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं होता। वे केवल उस हिंसक मानसिकता के शिकार बनते हैं जो सत्ता को मानवता से ऊपर मानती है। यह प्रश्न गंभीरता से पूछा जाना चाहिए कि आखिर राजनीतिक दल हिंसा का सहारा क्यों लेते हैं? जबकि इतिहास गवाह है कि हिंसा कभी स्थायी समाधान नहीं देती। हिंसा केवल भय, अविश्वास और प्रतिशोध को जन्म देती है। जो दल हिंसा को हथियार बनाते हैं, वे अंततः जनता की नजरों में अपना नैतिक अधिकार खो देते हैं। राजनीति का उद्देश्य समाज को जोड़ना

होना चाहिए, तोड़ना नहीं।

आज भारत एक नए वैश्विक दौर में प्रवेश कर रहा है। दुनिया भारत को एक उभरती आर्थिक शक्ति, तकनीकी महाशक्ति और लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में देख रही है। वर्ष 2047 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे करेगा, तब हमारा लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसे सभ्य और नैतिक राष्ट्र का निर्माण भी होना चाहिए जहां राजनीति का आधार अहिंसा, संवाद और संवेदनशीलता हो। यदि राजनीतिक दल नफरत, सांप्रदायिकता और हिंसा को अपना हथियार बनाए रखेंगे, तो विकसित भारत का सपना अधूरा रह जाएगा। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सांस्कृतिक चेतना रही है। गौतम बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया, महावीर ने अहिंसा को जीवन का सर्वोच्च मूल्य बताया, गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर साम्राज्य को चुनौती दी। यह वही भारत है जिसने दुनिया को यह सिखाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम व सह-अस्तित्व है। लेकिन आज राजनीतिक स्वार्थों व गैर-राजनीतिक आपराधिक तत्वों के कारण देश की छवि प्रभावित हो रही है। अपराधी मानसिकता के लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। वे दल बदलते रहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल शक्ति और स्वार्थ की पूर्ति होता है। बंगाल की ताजा घटनाओं में भी ऐसे तत्वों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।

समाधान केवल प्रशासनिक कठोरता में नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तन में निहित है। सबसे पहले सभी राजनीतिक दलों को सार्वजनिक रूप से हिंसा की निंदा करनी चाहिए और अपने कार्यकताओं को संयम बरतने का स्पष्ट संदेश देना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र प्रतिद्वंद्विता का नहीं, सह-अस्तित्व का नाम है। दूसरा, कानून व्यवस्था को लेकर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनानी होगी। किसी भी दल से जुड़े उपद्रवियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखकर संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क निगरानी बढ़ानी होगी। तीसरा, राजनीति के अपराधीकरण पर कठोर नियंत्रण आवश्यक है। ऐसे लोगों को राजनीतिक दलों में प्रवेश ही न मिले जिनकी पृष्ठभूमि हिंसक और आपराधिक रही हो। राजनीतिक दलों को अपने भीतर नैतिक अनुशासन विकसित करना होगा। चैथा, समाज में लोकतांत्रिक शिक्षा और संवेदनशीलता का वातावरण बनाना होगा। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं में संवाद, सहिष्णुता और अहिंसा के मूल्यों को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। जब तक समाज स्वयं हिंसा को अस्वीकार नहीं करेगा, तब तक राजनीतिक हिंसा का अंत कठिन होगा।

बंगाल की ताजा हिंसा केवल एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़ी एक गंभीर चेतावनी है। यदि हमने समय रहते राजनीति को स्वस्थ मूल्यों की ओर नहीं मोड़ा, तो नफरत और हिंसा लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती रहेंगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपनी आत्मा को पहचाने। यह देश युद्ध और प्रतिशोध की नहीं, बल्कि शांति, सह-अस्तित्व और विश्वबंधुत्व की भूमि है। 'वसुधैव कुटुम्बकम' केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता का मूल दर्शन है। यदि राजनीति इस दर्शन से विमुख होगी, तो लोकतंत्र केवल सत्ता संघर्ष बनकर रह जाएगा। पश्चिम बंगाल को अब हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति से बाहर निकलकर विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समरसता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही लोकतंत्र की गरिमा है, यही जनता की अपेक्षा है और यही विकसित भारत का मार्ग भी।

राहुल-अखिलेश पर टिकी 2029 की राजनीति

@ अजय कुमार

2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब देश ने विपक्षी गोलबंदी का एक महा-प्रयोग देखा था, तब उसका नाम था 'इंडिया गठबंधन' । यह प्रयोग बिना संदेह बड़ा था। 26 प्रमुख विपक्षी दलों को एक छत के नीचे लाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी त्रासदी यह रही कि इसे कभी कोई सर्वमान्य चेहरा या नेतृत्व नहीं मिल सका। 'विपक्ष का दूल्हा कौन बनेगा?' यह अंतहीन कलह गठबंधन की बुनियाद को ही खोखला करती रही। नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए तो ममता बनर्जी वीटो लगा देती हैं, राहुल गांधी के नाम पर सहमति बनती ही नहीं। नतीजा यह निकला कि बिखरा हुआ विपक्ष अपने-अपने राज्यों के किलों में सिमटकर रह गया, जिन्हें बीजेपी एक-एक करके ढहा रही है। आज जैसे-जैसे विपक्षी धुरंधर बारी-बारी चुनावी बिसात पर धराशायी हो रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस का 'डिफॉल्ट' दावा एक बार फिर पूरी ताकत से जिंदा हो गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का हालिया बयान इसी नैरेटिव की बानगी है। उन्होंने राहुल गांधी को 2029 का 'प्राइम-चैलेंजर' घोषित कर दिया है और कहा कि कांग्रेस सबसे पहले अपने सहयोगियों से इस बात पर सहमति बनाएगी। रेवंत की थ्योरी दिलचस्प है। वे लेफ्ट और क्षेत्रीय क्षत्रपों की हार में कांग्रेस की जीत देख रहे हैं। विडंबना यह है कि ये वही दल हैं जो कल तक 'इंडिया गठबंधन' में कांग्रेस के साझेदार थे और आज अपने-अपने राज्यों में बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसकर दम तोड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार इसका सबसे ताजा उदाहरण है। लोकसभा में टीएमसी ने किला बचा लिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव की चौखट पर आते ही बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के सामने उनकी सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गईं। बीजेपी ने यहां 206 सीटें जीतीं, जबकि टीएमसी 100 से नीचे लुढ़क गई। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से 15 हजार से ज्यादा वोटों से हार गईं। हाशिए पर खड़ी कांग्रेस को भले वहां दो सीटें मिलीं, लेकिन उसे इस बात का सुकून है कि बंगाल में अब टीएमसी का एकाधिकार खत्म हो चुका है। दिल्ली और पंजाब से कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने वाले अरविंद केजरीवाल का सपना 'तीसरा विकल्प' बनने का था। फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी करते हुए आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त दी। 70 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि आप 22 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस आज इस गणित पर खुश हो सकती है कि जो भी जमीन आप खोएगी, वह आखिरकार कांग्रेस की झोली में ही गिरेगी। नीतीश कुमार ने 2024 से पहले विपक्ष को एक धागे में पिरोने के लिए देशव्यापी दौरे किए थे, लेकिन केंद्रीय राजनीति में उनका नेतृत्व स्थापित होने से पहले ही सहयोगियों के अविश्वास ने उनकी जमीन खिसका दी। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।

अब रह गई केवल एक दीवार अखिलेश यादव। वे राहुल गांधी के लिए एक जटिल पहेली हैं। चुनौती इसलिए हैं क्योंकि वे देश के सबसे बड़े सियासी सूबे, उत्तर प्रदेश, के निर्विवाद नायक हैं। यह वही यूपी है जिसने 2024 में बीजेपी के रथ को रोककर उसे बहुमत से दूर कर दिया था। अखिलेश आज विपक्ष के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके पास कोर 'मुस्लिम-यादव' वोटबैंक की अचूक ताकत है, एक मजबूत संगठन है और वे सीधे योगी-मोदी की जोड़ी की आंखों में आंखें डालकर लड़ रहे हैं। 2024 में कांग्रेस को यूपी में जो भी संजीवनी मिली, उसका पूरा श्रेय अखिलेश के

खाते में जाता है। इस कड़वे सच के बावजूद, राहुल गांधी के लिए राहत की बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने उनके साथ कभी वह 'अहंकार और तिरस्कार' का रवैया नहीं अपनाया, जो ममता बनर्जी ने बंगाल में दिखाया। अखिलेश खुद यूपी की सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए वे दिल्ली की रेस के लिए कांग्रेस से फिलहाल कोई नया मोर्चा नहीं खोलना चाहते। असल परीक्षा 2027 में होगी। यदि अखिलेश 2027 में यूपी फतह कर लेते हैं, तो वे राष्ट्रीय क्षितिज पर राहुल गांधी से कहीं बड़े कद के नेता बनकर उभरेंगे। वे 2027 की तैयारी कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यूपी में अगले वर्ष समाजवादी सरकार बनने जा रही है। लेकिन यदि वे नाकाम रहे, तो राहुल गांधी 2029 के लिए 'निर्विरोध चैलेंजर' बन जाएंगे।

क्षेत्रीय दलों की त्रासदी यह है कि उनकी प्रासंगिकता सिर्फ उनके राज्य की सत्ता से है, जबकि कांग्रेस के लिए 'ब्रांड राहुल' राज्यों की हार-जीत के नफे-नुकसान से बहुत ऊपर है। 2024 में 99 सीटें जीतकर कांग्रेस ने ऐसा जश्न मनाया था, मानो देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने पुराने वैभव में लौट आई हो। लेकिन यह भ्रम जल्द ही टूट गया। हरियाणा में जीत का हलवा तैयार था, पर कांग्रेस की आपसी गुटबाजी और बीजेपी की माइक्रो-प्लानिंग ने बाजी पलट दी। इसके बाद पराजय का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। महाराष्ट्र और बिहार में कांग्रेस सबसे निचले पायदान पर खिसक गई। गनीमत बस इतनी रही कि उसके मजबूत सहयोगी राजद, उद्धव शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी भी खुद को बचा नहीं पाए। तमिलनाडु में जब डीएमके का जहाज डूबने लगा, तो चतुर कांग्रेस ने समय रहते पाला बदलकर पांच विधायकों के साथ सत्ता के नए जहाज पर छलांग लगा दी। हाल ही में डीएमके ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने की घोषणा की है और लोकसभा में अलग बैठने की मांग की है। डीएमके और कांग्रेस का 20 साल पुराना रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया। पूरी तस्वीर का सबसे दिलचस्प और विरोधाभासी पहलू यही है कि देशभर में स्थितियां कांग्रेस के अनुकूल हो रही हैं, लेकिन इस खेल में कांग्रेस का अपना कोई पराक्रम नहीं है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी क्षेत्रीय दलों और वामपंथ के जिस सफाए पर संतोष जता रहे हैं, वह जमीन कांग्रेस ने नहीं, बल्कि बीजेपी ने जीती है। बिहार में नीतीश, बंगाल में ममता, दिल्ली में केजरीवाल और अगर स्थितियां ऐसी ही रहीं, तो 2027 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश बीजेपी एक-एक करके राहुल के सभी आंतरिक प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटा रही है। लब्बोलुआब यह है कि यदि राहुल गांधी की उम्मीदें अपने संगठन की ताकत से ज्यादा बीजेपी की आक्रामक विस्तारवादी नीति पर टिकी हैं, तो यह बहुत खतरनाक है। राहुल गांधी की राह के कांटे खुद पीएम मोदी ही दूर कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी को विपक्ष का इकलौता सुल्तान बनाने का सेहरा, अनजाने में ही सही, बीजेपी के सिर ही सजेगा। विपक्ष का भविष्य अब अखिलेश यादव और 2027 के यूपी चुनाव पर टिका है यही राजनीति का चक्रव्यूह है।

महाराजा अग्रसेन ट्रस्टः सेवा और

@ राष्ट्र समाज

'सेवा ही धर्म है', इस पावन विचार को अपने आचरण में ढालना जितना कठिन है, इसे एक संस्था के रूप में धरातल पर उतारना उतना ही चुनौतीपूर्ण। लेकिन 'महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट (पंजी), पंजाबी बाग' ने पिछले चार दशकों से इस सिद्धांत को न केवल जिया है, बल्कि देश में चैरिटेबल हेल्थकेयर (परमार्थ चिकित्सा) की एक नई परिभाषा भी लिखी है। वर्ष 1980 में एक छोटे से संकल्प के साथ शुरू हुआ यह ट्रस्ट आज देश के अग्रणी और सबसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थानों में गर्व से अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। वर्तमान समय में इस विशाल सेवा यात्रा को एक नया गौरव मिला है ट्रस्ट की अध्यक्ष डॉ. मीना सुभाष गुप्ता जी के रूप में। उनके कुशल, संवेदनशील और दूरदर्शी नेतृत्व में इस चैरिटेबल ट्रस्ट ने आधुनिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज उनकी देखरेख में ट्रस्ट की सभी इकाइयां सेवा,

चिकित्सा के 40 साल

गुणवत्ता, अनुशासन और जनता के विश्वास का नया मानदंड बन चुकी हैं। आज 'महाराजा अग्रसेन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स' केवल एक नाम नहीं, बल्कि दिल्ली-एनसीआर सहित देश के लाखों परिवारों के भरोसे का केंद्र बन चुका है। आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं, सामाजिक सरोकार और चिकित्सा शिक्षा के संगम के रूप में इस ग्रुप के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख संस्थान पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं:

- **महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली**
- **महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, द्वारका, नई दिल्ली**
- **महाराजा अग्रसेन सत नारायण गुप्ता हॉस्पिटल, बहादुरगढ़**
- **महाराजा अग्रसेन मेडिकल यूनिवर्सिटी**
- **महाराजा अग्रसेन केदारनाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज**
- **महाराजा अग्रसेन राजेश गुप्ता नर्सिंग कॉलेज**
- **महाराजा अग्रसेन माता नारायणी देवी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र**

चिकित्सा के साथ-साथ नर्सिंग और उच्च मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में यह विस्तार बताता है कि ट्रस्ट देश को भविष्य के कुशल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ देने के लिए भी पूरी तरह तैयार है।

65 बेड से सुपर-स्पेशियलिटी तक का सफर

अगर हम इस सेवा यात्रा के उद्गम की बात करें, तो पश्चिमी दिल्ली का पंजाबी बाग स्थित 'महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल' आज आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का एक चमकता हुआ गौरव है। इसकी शुरूआत वर्ष 1991 में महज 65 बेड के एक छोटे से अस्पताल के रूप में हुई थी। लेकिन समर्पण और ईमानदारी के बल पर यह अस्पताल आज एक विशाल मल्टी सुपर-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का रूप ले चुका है। किसी भी अस्पताल की असली ताकत उसकी इमारत या मशीनें नहीं, बल्कि उसका स्टाफ होता है। इस अस्पताल की पिछले चार दशकों की सबसे बड़ी पूंजी इसके अनुभवी, कुशल और समर्पित डॉक्टरों की टीम रही है। वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ के मानवीय दृष्टिकोण ने ही इसे पश्चिमी दिल्ली का सबसे भरोसेमंद अस्पताल बनाया है। यहां आने वाले मरीजों को केवल कागजी पर्चों पर इलाज नहीं मिलता, बल्कि उन्हें एक आत्मीय, संवेदनशील और सुरक्षित माहौल का अहसास कराया जाता है।

वैश्विक स्तर की चिकित्सा सुविधाएं

चैरिटेबल होने का मतलब यह कतई नहीं है कि तकनीक से समझौता किया जाए। डॉ. मीना सुभाष गुप्ता के मार्गदर्शन में अस्पताल को दुनिया की बेहतरीन और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। आज यहाँ एक ही छत के नीचे जटिल से जटिल इलाज संभव हैं, जिनमें शामिल हैं: कार्डियलजी (हृदय रोग), तंत्रिका-विज्ञान (नसों के रोग), हड्डी रोग, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रिटिकल केयर, आपातकालीन चिकित्सा, और जोड़ प्रत्यारोपण जैसी सुपर-स्पेशियलिटी सेवाएं। इतना ही नहीं, गंभीर बीमारियों के लिए यहाँ 'किडनी' (गुर्दा) और 'हार्ट' (हृदय) ट्रांसप्लांट जैसी बेहद जटिल और उन्नत सर्जरी भी सफलतापूर्वक की जा रही हैं। गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए यहां अत्याधुनिक आईसीयू, पीआईसीयू (बच्चों का आईसीयू), एनआईसीयू (नवजात शिशुओं का आईसीयू), आधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सर्विसेज, मॉलिक्यूलर लैब और उन्नत ईसीएमओ फैसिलिटी (कृत्रिम फेफड़ा/हृदय प्रणाली) जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं मौजूद हैं, जो इसे देश के अग्रणी स्वास्थ्य केंद्रों की कतार में खड़ा करती हैं।

कब तक दोहराई जाती रहेंगी निर्भया जैसी त्रासदियां?

@ राष्ट्र समाज

दिल्ली के नांगलोई में एक निजी बस के भीतर महिला के साथ हुई बस कंडक्टर एवं ड्राइवर के दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया है। यह घटना केवल एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि उस भयावह सामाजिक और प्रशासनिक विफलता का आईना है, जो वर्षों से हमारे सामने खड़ी है। चौदह वर्ष पहले निर्भया कांड के बाद देश की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा था। लोगों ने सोचा था कि अब व्यवस्था बदलेगी, कानून सख्त होंगे, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और समाज अपनी सोच बदलेगा। लेकिन आज जब उसी प्रकार की घटनाएं पुनः पुनः सामने आती हैं, तब यह प्रश्न और भी तीखा होकर उठता है कि आखिर हम बदले कहां हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बार-बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसका उत्तर केवल कानून की कमजोरी में नहीं, बल्कि समाज की उस विकृत मानसिकता में छिपा है, जहां महिला को आज भी बराबरी के सम्मान के साथ नहीं देखा जाता। आधुनिकता के चमकदार दावों के बीच भी पुरुष प्रधान सोच का अंधेरा जस का तस मौजूद है। महिलाओं को व्यक्ति नहीं, बल्कि उपभोग की वस्तु मानने वाली सोच आज भी अनेक मन-मस्तिष्कों में गहराई तक बैठी हुई है। यही कारण है कि सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों, स्कूल-कॉलेजों और यहां तक कि घरों के भीतर भी महिलाएं असुरक्षा का अनुभव करती हैं।

विडंबना यह है कि विज्ञान, तकनीक और आर्थिक विकास के इस दौर में भी समाज स्त्री के सम्मान और सुरक्षा के बुनियादी संस्कार विकसित नहीं कर पाया। बच्चों को शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन संवेदनाएं नहीं दी जा रहीं। घरों में बेटियों पर नियंत्रण और बेटों को छूट देने वाली मानसिकता आज भी कायम है। एक ओर लड़कियों को 'सावधान रहने' की नसीहत दी जाती है, दूसरी ओर लड़कों को अपने व्यवहार और दृष्टि की मयार्दा सिखाने की गंभीर कोशिश बहुत कम दिखाई देती है। यही असंतुलन आगे चलकर अपराधों की जमीन तैयार करता है। प्रश्न यह भी है कि प्रशासन बार-बार ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम क्यों हो रहा है? निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे। सीसीटीवी कैमरे, महिला हेल्पलाइन, फास्ट ट्रैक कोर्ट, पुलिस गश्त और सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा उपायों की लंबी घोषणाएं हुईं। लेकिन वास्तविकता यह

है कि इन व्यवस्थाओं का बड़ा हिस्सा कागजों और भाषणों तक सीमित रह गया। निजी बसें आज भी बिना पर्याप्त निगरानी के चल रही हैं। कई स्थानों पर चालक और परिचालकों का समुचित सत्यापन तक नहीं होता। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन अक्सर केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है।

दुनियाभर में बालिकाओं के अस्तित्व एवं अस्मिता के लिये जागरूकता एवं आन्दोलनों के बावजूद बालिकाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसा ही हो रहा है, बालिकाओं की स्थिति, लड़कियों की तुलना में लड़कों की बढ़ती संख्या, तलाक के बढ़ते मामले, गांवों में बालिका की अशिक्षा, कुपोषण एवं शोषण, बालिकाओं की सुरक्षा, बालिकाओं के साथ होने वाली बलात्कार की घटनाएं, अश्लील हरकतें और विशेष रूप से उनके खिलाफ होने वाले अपराधों पर प्रभावी चर्चा एवं कठोर निर्णयों से एक सार्थक वातावरण का निर्माण किये जाने की अपेक्षा है। क्योंकि एक टीस-सी मन में उठती है कि आखिर महिलाएं एवं बालिकाओं कब तक भोग की वस्तु बनी रहेगी? उसका जीवन कब तक खतरों से घिरा रहेगा? बलात्कार, छेड़खानी, भ्रूण हत्या और दहेज की धधकती आग में वह कब तक भस्म होती रहेगी? कब तक उसके अस्तित्व एवं अस्मिता को नौचा जाता रहेगा?

सच्चाई यह है कि हमारी व्यवस्था अपराध होने के बाद सक्रिय होती है, अपराध रोकने के लिये नहीं। हर बार घटना के बाद गिरफ्तारी, जांच और बयानबाजी होती है, लेकिन अपराध की जड़ों तक पहुंचने की गंभीर पहल नहीं दिखाई देती। राजनीतिक दल कुछ दिनों तक आरोप-प्रत्यारोप करते हैं, मीडिया में बहस चलती है और फिर धीरे-धीरे सब कुछ सामान्य मान लिया जाता है। लेकिन जिन परिवारों की बेटियां इस अमानवीयता का शिकार होती हैं, उनके जीवन में भय, पीड़ा और असुरक्षा स्थायी घाव बनकर रह जाते हैं।

यह भी विचारणीय है कि आखिर महिलाएं और बालिकाएं बार-बार ऐसे अत्याचारों का शिकार क्यों बन रही हैं? इसका कारण केवल अपराधियों की क्रूरता नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनहीनता भी है। सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सामूहिक जिम्मेदारी का अभाव दिखाई देता है। लोग तमाशबीन बन जाते हैं। कई बार पीड़िता को ही कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है-उसके कपड़े, समय, जीवनशैली और व्यवहार पर सवाल उठाए जाते हैं। यह मानसिकता अपराधियों का मनोबल बढ़ाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समाज पूरी तरह पीड़िता के साथ खड़ा नहीं होगा। कब तक महिलाएं अपने ही शहरों, बसों, गलियों और कार्यस्थलों पर भय के साथ जीती रहेंगी? कब तक माता-पिता अपनी बेटियों के घर लौटने तक चिंता में डूबे रहेंगे? यह प्रश्न केवल महिलाओं का नहीं, बल्कि पूरे समाज की आत्मा का प्रश्न है। जिस समाज में आधी आबादी स्वयं को सुरक्षित महसूस न करे, वह समाज वास्तव में सभ्य नहीं कहलाया जा सकता।

आज आवश्यकता केवल कठोर कानूनों की नहीं, बल्कि कठोर सामाजिक आत्ममंथन की है। कानून अपराधी को दंड दे सकता है, लेकिन समाज ही मानसिकता बदल सकता है। स्कूलों और परिवारों में लैंगिक संवेदनशीलता की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। बेटियों को भय में जीना नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक जीना सिखाना होगा। फिल्मों, सोशल मीडिया और विज्ञापनों में स्त्री की वस्तुवादी छवि पर भी गंभीर विमर्श जरूरी है, क्योंकि संस्कृति और मनोरंजन भी समाज की सोच को प्रभावित करते हैं। प्रशासन को भी केवल घटनाओं के बाद की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन में रियल-टाइम जीपीएस, सीसीटीवी, पैनिक बटन और नियमित निगरानी को पूरी कठोरता से लागू करना होगा। निजी परिवहन संचालकों और कर्मचारियों का गहन सत्यापन अनिवार्य किया जाना चाहिए। पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और सक्रिय बनाना होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि समाज को यह समझना होगा कि महिला सुरक्षा कोई 'महिला मुद्दा' नहीं, बल्कि मानवता और सभ्यता का प्रश्न है। जब तक स्त्री को समान सम्मान, स्वतंत्रता व सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक विकास के सारे दावे अधूरे रहेंगे।

नांगलोई की यह घटना केवल एक समाचार नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। यदि अब भी हम नहीं जागे, तो निर्भया जैसी त्रासदियां बार-बार हमारे सामने आती रहेंगी हर बार हमारी संवेदनहीनता, हमारी प्रशासनिक विफलता और हमारी विकृत मानसिकता हमें कठघरे में खड़ा करती रहेगी। प्रश्न यही है- आखिर कब तक? तमाम जागरूकता एवं सरकारी प्रयासों के बावजूद भारत में भी बालिकाओं की स्थिति में यथोचित बदलाव नहीं आया है। धर्मगुरु, राजनेता एवं समाज सुधारक महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति कितनी कुत्सित मानसिकता का परिचय देते आए हैं, यह किसी से छिपा नहीं है।

इनके चरित्र का दोहरापन जगजाहिर हो चुका है। कोई क्या पहने, क्या खाए, किससे प्रेम करे और किससे शादी करें, सह-शिक्षा का विरोधी नजरिया- इस तरह की पुरुषवादी सोच के तहत बालिकाओं को उनके हकों से वंचित किया जा रहा है, उन पर तरह-तरह की बंदिशें एवं पहरे लगाये जा रहे हैं। 'यत्र पूज्यंते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता'- जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। हम देखते हैं कि नारी का हर जगह अपमान होता चला जा रहा है। 'भोग की वस्तु' समझकर आदमी 'अपने तरीके' से 'इस्तेमाल' कर रहा है, यह बेहद चिंताजनक बात है। आज अनेक शक्लों में नारी के वजूद को धुंधलाने की घटनाएं शक्ल बदल-बदल कर काले अध्याय रच रही है। देश में गैंग रेप की वारदातों में कमी भले ही आयी हो, लेकिन उन घटनाओं का रह-रह कर सामने आना त्रासद एवं दुःखद है।

यूपी में ब्राह्मण वोटरों के लिए सजते सियासी गुलदस्ते

@ अजय कुमार

उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज एक बार फिर केंद्र में आ गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगभग सभी प्रमुख दल इस समाज को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुट गये हैं। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का मजबूत आधार माने जाने वाले ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर अब विपक्षी दलों को यह उम्मीद दिखाई दे रही है कि उनमें कुछ नाराजगी पनप रही है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही अपने-अपने तरीके से ब्राह्मण समाज को साधने में लगी हुई हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी यह समझती है कि यदि ब्राह्मण मतदाता बड़ी संख्या में उससे दूर हुए तो उसका चुनावी गणित प्रभावित हो सकता है। इसलिए सत्ता पक्ष भी लगातार संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार यह संदेश देने में लगे हैं कि वर्तमान सरकार में एक खास जाति का प्रभाव बढ़ गया है और ब्राह्मण समाज स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहा है। सपा यह धारणा बनाने का प्रयास कर रही है कि प्रशासनिक तंत्र

में ठाकुर समाज के अधिकारियों का दबदबा है और उन्हें बेहतर पदों पर तैनाती मिल रही है। कानून व्यवस्था से जुड़े कुछ मामलों को भी इसी दृष्टि से प्रचारित किया जा रहा है ताकि ब्राह्मण मतदाताओं के भीतर असंतोष पैदा किया जा सके। लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या उसका अपना पुराना इतिहास है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्मृतियां बहुत जल्दी धुंधली नहीं होतीं। बड़ी संख्या में ब्राह्मण मतदाता आज भी उस दौर को याद करते हैं जब सपा की सरकार पर गुंडाराज, जातीय पक्षपात और कानून व्यवस्था बिगड़ने के आरोप लगते थे। उस समय कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्हें विपक्ष ने ब्राह्मण विरोधी वातावरण के रूप में प्रचारित किया। यही वजह है कि सपा चाहे जितनी कोशिश करें, उसके सामने भरोसे का संकट बना हुआ है। स्थिति तब और कठिन हो जाती है जब पार्टी के कुछ नेता विवादित बयान दे देते हैं। सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार भाटी का हालिया बयान इसी श्रेणी में देखा जा रहा है,

जिसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज की तुलना अपमानजनक तरीके से की। ऐसे बयान सपा की उस कोशिश को कमजोर करते हैं, जिसमें वह स्वयं को ब्राह्मण हितैषी साबित करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केवल सम्मेलनों और नारों से कोई समाज प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह नेताओं की भाषा व व्यवहार को भी देखता है। पार्टी के भीतर विरोधाभासी संकेत मिलें तो मतदाताओं का भरोसा बन पाना कठिन हो जाता है।

बसपा की प्रमुख मायावती भी इस समय ब्राह्मण वोटरों पर विशेष ध्यान दे रही हैं। एक समय ऐसा था जब बहुजन समाज पार्टी ने दलित और ब्राह्मण सामाजिक समीकरण के सहारे उत्तर प्रदेश की सत्ता प्राप्त की थी। उस दौर में 'ब्राह्मण शंख बजायेगा, हाथी बढ़ता जायेगा' जैसे नारे खूब चर्चित हुए थे। पार्टी ने बड़ी संख्या में ब्राह्मण नेताओं को आगे बढ़ाया और उन्हें सम्मानजनक हिस्सेदारी भी दी। हालांकि बसपा के सामने भी विरोधाभास की समस्या है। राजनीतिक विरोधियों को आज भी उसका पुराना नारा 'तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार' याद है। विरोधी दल यह सवाल उठाते हैं कि जो पार्टी कभी ब्राह्मण विरोधी नारे लगाती थी, वह आज अचानक ब्राह्मण हितैषी कैसे बन गयी। यही कारण है कि मायावती लगातार समाजवादी पार्टी को घेरते हुए स्वयं को अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हैं। मायावती समझती हैं कि यदि ब्राह्मण मतदाता भाजपा से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें आकर्षित करने का अवसर अभी भी मौजूद है। इसलिए वह सपा पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव से अपने नेताओं के बयानों पर माफी मांगने की मांग कर रही हैं। यह केवल राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। बसपा चाहती है कि ब्राह्मण समाज के भीतर यह संदेश जाए कि सपा केवल चुनावी लाभ के लिए उन्हें याद कर रही है, जबकि उसके नेताओं की मानसिकता अब भी वही है। उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से देख रहे हैं। भाजपा की राजनीति लंबे समय से सामाजिक संतुलन पर आधारित रही है। पार्टी यह भलीभांति जानती है कि उत्तर प्रदेश में केवल एक जाति के सहारे सत्ता में बने रहना संभव नहीं है। ब्राह्मण समाज भाजपा का परंपरागत समर्थक माना जाता रहा है और यदि उसमें नाराजगी का संदेश फैलता है तो उसका असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। इसी कारण हाल के मंत्रिमंडल विस्तार में ब्राह्मण चेहरे मनोज पाण्डेय को मंत्री बनाकर भाजपा ने स्पष्ट संकेत देने की कोशिश की कि पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है। भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि सरकार में ब्राह्मण समाज की भागीदारी और सम्मान दोनों सुरक्षित हैं। इसके अलावा पार्टी संगठन में भी ब्राह्मण नेताओं की सक्रियता बढ़ायी जा रही है। भाजपा की चिंता यह है कि विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि वर्तमान सरकार में ठाकुर समाज का प्रभाव अधिक है। कई प्रशासनिक नियुक्तियों और पुलिस कार्यवाहियों को लेकर भी सवाल उठाये गये हैं। लेकिन भाजपा समर्थकों का कहना है कि योगी सरकार ने जाति के बजाय कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई बिना भेदभाव के की गयी है। भाजपा का तर्क यह भी है कि यदि केवल जातीय आधार पर शासन चल रहा होता तो उसे लगातार व्यापक जनसमर्थन नहीं मिलता।

बहरहाल, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को लेकर तीनों प्रमुख दलों में रस्साकशी इसलिये हो रही है क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या भले ही बहुत अधिक न हो, लेकिन उसका राजनीतिक प्रभाव काफी व्यापक माना जाता है। यह समाज केवल वोट देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामाजिक , वैचारिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। यही कारण है कि हर दल उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को देखें तो ब्राह्मण मतदाता पूरी तरह किसी एक दल के साथ बंधा हुआ नहीं दिख रहा। वह अपने सम्मान, भागीदारी और सुरक्षा को लेकर सजग है। लेकिन साथ ही वह पुराने अनुभवों को भी याद रखता है। सपा के सामने चुनौती यह है कि वह केवल आरोपों के सहारे नहीं, बल्कि व्यवहार और नेतृत्व की विश्वसनीयता के माध्यम से भरोसा पैदा करे। बहुजन समाज पार्टी को अपने पुराने नारों और छवि से बाहर निकलना होगा। वहीं भाजपा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके खिलाफ फैलाई जा रही उपेक्षा की धारणा मजबूत न हो। कुल मिलाकर, 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव केवल विकास और कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं होगा, बल्कि सामाजिक संतुलन और राजनीतिक विश्वास की भी परीक्षा बनेगा। ब्राह्मण मतदाता इस बार किस ओर जायेगा, अभी स्पष्ट नहीं है, इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता उसके रुख से जरूर प्रभावित होगा। सभी दलों के नेताओं ने ब्राह्मण वोटों के लिये सियासी गुलदस्ते तैयार कर रखे हैं। देखना यह है कि 2027 में ब्राह्मण वोटर किसका गुलदस्ता स्वीकार करेगा।

मिलिए जौनपुर के नए डीएम सैमुअल पॉल एन से

@ बाल मुकुंद ओझा

उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक बिसात पर हाल ही में हुए फेरबदल ने जौनपुर को एक नया नेतृत्व दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के तेजतर्रार अधिकारी सैमुअल पॉल एन को जौनपुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र के लोक निर्माण विभाग में विशेष सचिव के पद पर तबादले के बाद, अब जौनपुर के विकास और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी सैमुअल पॉल के कंधों पर होगी।

तकनीकी समझ और प्रशासनिक अनुभव का संगम: 23 अगस्त 1985 को जन्मे सैमुअल पॉल एन उस नई पीढ़ी के नौकरशाहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समस्याओं को सिर्फ प्रशासनिक चश्मे से नहीं, बल्कि तकनीकी और व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने के कारण उनकी कार्यशैली में एक खास तरह की सटीकता और डेटा-आधारित निर्णय लेने की क्षमता दिखाई देती है।

आज के डिजिटल युग में, जब सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन 'स्मार्ट गवर्नेंस' के जरिए हो रहा है, उनकी यह शैक्षणिक योग्यता जौनपुर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है।

कानपुर से जौनपुर तक का सफर: जौनपुर की कमान संभालने से पहले, सैमुअल पॉल एन उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्र कानपुर नगर में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। वह 21 फरवरी 2023 से वहां प्रबंध निदेशक और अतिरिक्त आयुक्त श्रेणी के पद पर तैनात थे। कानपुर जैसे बड़े और जटिल औद्योगिक शहर में उनका कार्यकाल काफी सराहनीय रहा, जहां उन्होंने शहरी विकास, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उनके इसी अनुभव को देखते हुए शासन ने उन्हें जौनपुर की कमान सौंपी है।

जौनपुर में चुनौतियां और उम्मीदें: एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले जिले के रूप में जौनपुर की अपनी अनूठी पहचान है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ बुनियादी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई चुनौतियां भी हैं। निर्वर्तमान डीएम डॉ. दिनेश चंद्र ने अपने कार्यकाल में विकास कार्यों को जो गति दी थी, उसे बरकरार रखते हुए नए आयामों तक ले जाना सैमुअल पॉल की प्राथमिकता होगी।

एक इंजीनियर का दिमाग और एक अनुभवी कमिश्नर का दृष्टिकोण—यही वो संतुलन है जो सैमुअल पॉल एन को एक जन-हितैषी अधिकारी बनाता है। जौनपुर की जनता को नए जिलाधिकारी से काफी उम्मीदें हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कानपुर की औद्योगिक रफ्तार को करीब से देखने वाले सैमुअल पॉल, जौनपुर की मिट्टी और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में विकास का कौन सा नया अध्याय लिखते हैं।

Haldiram's
Banao
CHATPATE
PAL AUR
MEETHI
Yaadein!
TRADITION IN EVERY BITE,
HAPPINESS IN EVERY MOMENT.
Crafted with the finest ingredients and authentic recipes.
A perfect blend of savoury snacks and traditional sweets.
Hygienically prepared and packed for your safety.
Loved by millions for generations.
Perfect for every occasion, celebration and craving.
Bringing joy, taste and togetherness to your everyday moments.
From our kitchen to your heart – the Haldiram's promise.
REAL INGREDIENTS. GREAT TASTE. TIMELESS TRADITION.
Taste the tradition. Share the happiness. !
Shop Online @ www.haldiramsonline.com

बिट्टू टिक्की वाला की सफलता की अनोखी दास्तान

@ राष्ट्र समाज

दिल्ली की सड़कों पर कभी स्वाद का तड़का लगाने वाले एक छोटे से ठेले से शुरू हुआ सफर आज देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित फूड ब्रांड्स में से एक बन चुका है। हम बात कर रहे हैं 'बिट्टू टिक्की वाला' यानी की। स्वाद के शौकीनों के दिलों पर राज करने वाला यह नाम आज सिर्फ चाट-टिक्की तक सीमित नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट जगत के लिए सफलता की एक बेमिसाल केस स्टडी बन चुका है। यह कहानी इस बात की जिंदा गवाही है कि कैसे सही विजन, अटूट हौसले और कड़ी मेहनत के दम पर एक अदना सा ठेला ₹300 करोड़ के टर्नओवर वाले विशाल कमर्शियल साम्राज्य में तब्दील हो सकता है।

इस स्वाद के साम्राज्य की नींव दो मजबूत स्तंभों पर टिकी है। कंपनी के सीएमडी मिस्टर एस. आर. यादव, जो कभी दिल्ली में बच्चों का भविष्य संवारने वाले एक शिक्षक थे, भाग्य की रेखाओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि इंसान का कर्म ही उसका भाग्य लिखता है। उनके इसी विजन को धरातल पर उतारने के लिए कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर आर. के. यादव रोजाना 18-18 घंटे की अथक मेहनत करते हैं। एक शिक्षक के रणनीतिक दिमाग और दूसरे साथी की बेजोड़ कर्मठता के इसी अनूठे संगम ने को एक घरेलू नाम बना दिया।

स्वाद की दुनिया में गुणवत्ता और शुद्धता के सख्त मानकों के दम पर इस ब्रांड ने आम सड़कों से निकलकर देश के सबसे आलीशान महलों और वीआईपी गलियारों तक अपनी पैठ बनाई है। मुंबई में मुकेश अंबानी के भव्य निवास 'एंटीलिया' में चाट का जलवा बिखेरना

हो या जामनगर (वंतारा) में अनंत अंबानी के जन्मदिन के भव्य जश्न में मेहमानों का दिल जीतना हो, की कैटरिंग ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में उबेर-2 के उद्घाटन के ऐतिहासिक मौके पर भी कैटरिंग का जिम्मा इसी कंपनी के कंधों पर था। भारत सरकार की तमाम मिनिस्ट्रीज में रोजाना हजारों की संख्या में कैटरिंग करने से लेकर उदयपुर व गुरुग्राम जैसे शहरों के 5-स्टार होटलों तक, स्वदेशी ब्रांड की साख पैन-इंडिया लेवल पर गूंज रही है।

अगर आंकड़ों के आईने में देखें, तो आज बी टी डब्ल्यू एक बहुत बड़ी फूड चेन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। कंपनी का सालाना टर्नओवर जहां ₹300 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है, वहीं इसके पास 1800 से अधिक कर्मचारियों का एक विशाल और कुशल परिवार है।

इस स्वाद को तैयार करने के लिए 1,00,000 स्क्वायर मीटर के विशाल क्षेत्र में फैली एक अत्याधुनिक फैक्ट्री काम कर रही है, जबकि दिल्ली-एनसीआर के 'द अशोक होटल', पीतमपुरा, बकोली और सोनीपत (राई) जैसी चार प्रमुख जगहों से इसका कॉर्पोरेट संचालन होता है। 22 रिटेल आउटलेट्स के जरिए जनता को अपनी सेवाएं दे रहा यह ब्रांड साबित करता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। 'बिट्टू टिक्की वाला' की यह जादुई यात्रा आज के दौर में स्टार्टअप शुरू करने वाले देश के करोड़ों युवाओं के लिए आंत्रप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी और व्यावहारिक प्रेरणा है।

SAKARNI PLASTER (INDIA) PRIVATE LIMITED

D Mall 405, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034

customercare@sakarni.com | +91-9810177365 | www.sakarni.com

मोदी के आह्वान में राजनीति?

@ ललित गर्ग

आज पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां युद्ध, आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट और वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं ने मानव सभ्यता को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है। खाड़ी देशों में लंबे समय से चल रहे संघर्ष और युद्ध की विभीषिका ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरे तक प्रभावित किया है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलाओं का बाधित होना, डॉलर के मुकाबले विभिन्न देशों की मुद्राओं का कमजोर होना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्पन्न असंतुलन ने लगभग हर राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। भारत भी इन परिस्थितियों से अछूता नहीं रह सकता। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है और सोने का भी विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन के संयमित उपयोग और सोने की खरीद को सीमित करने का आह्वान केवल एक आर्थिक सलाह नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में किया गया दूरदर्शी चिंतन है। दुर्भाग्य यह है कि मोदी की मितव्ययिता की अपील पर पूरे देश को एकजुट होकर गंभीरता से विचार करना चाहिए था, उस विषय को भी राजनीतिक विवाद का हथियार बना दिया गया। कुछ विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री की इस अपील को जनता में भय फैलाने वाला कदम बताया, तो कुछ ने इसे सरकार की विफलताओं को छिपाने का प्रयास कहा। जबकि वस्तुतः यह अपील राष्ट्र को भविष्य की संभावित चुनौतियों के प्रति सचेत करने और समय रहते आत्मानुशासन अपनाने का संदेश है। यह राजनीति का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी का प्रश्न है। जब विश्व के बड़े-बड़े राष्ट्र आर्थिक संकटों से जूझ रहे हों, तब भारत के प्रधानमंत्री यदि नागरिकों को संयम एवं मितव्ययिता का सूत्र देते हैं तो उसे राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यह पहला अवसर नहीं है, जब प्रधानमंत्री ने देश की तरक्की को बनाए रखने की सामूहिक चिन्ता करते हुए मितव्ययिता एवं संयम की अपील की हो।

भारत की संस्कृति मूलतः संयम प्रधान रही है। भारतीय जीवन-दर्शन में संयम को केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। हमारे ऋषियों, मुनियों और महापुरुषों ने सदैव आवश्यकता और विलासिता के बीच अंतर करना सिखाया। महावीर, बुद्ध, गांधी और विनोबा भावे जैसे महापुरुषों ने त्याग और संयम को ही मानवता की सबसे बड़ी शक्ति बताया। भारतीय संस्कृति कहती है कि जितना आवश्यक हो उतना ही उपभोग करो, क्योंकि असीमित उपभोग अंततः संकट को जन्म देता है। यही कारण है कि भारतीय सभ्यता हजारों वर्षों तक टिकाऊ और संतुलित बनी रही। आज जब पूरी दुनिया उपभोक्तावाद के दुष्परिणाम भुगत रही है, तब भारत की यही संयम आधारित संस्कृति समाधान का मार्ग दिखा सकती है। सोने के प्रति भारतीय समाज का आकर्षण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर गहरा रहा है। विवाह, पारिवारिक उत्सव, धार्मिक परंपराएं और सामाजिक प्रतिष्ठा में सोने का विशेष स्थान है। लेकिन यह भी एक कठोर सत्य है कि भारत का अधिकांश सोना आयातित होता है। हर वर्ष अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार सोने के आयात पर खर्च होता है। यह सोना उत्पादन या औद्योगिक विकास में उपयोग होने के बजाय घरों और लॉकरों में बंद होकर निष्क्रिय पड़ा रहता है। ऐसे समय में जब विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा हो और रुपये की कीमत लगातार गिर रही हो, तब सोने की खरीद में संयम बरतने की अपील आर्थिक दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक है। यह किसी की परंपराओं के विरोध में नहीं, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती के पक्ष में उठाया गया कदम है।

इसी प्रकार ईंधन के उपयोग में संयम भी समय की आवश्यकता है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयातित तेल पर निर्भर है। खाड़ी देशों में युद्ध और अस्थिरता के कारण तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका सीधा प्रभाव पेट्रोल, डीजल,

परिवहन, उद्योग और महंगाई पर पड़ता है। यदि नागरिक ईंधन के अनावश्यक उपयोग को सीमित करें, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, ऊर्जा बचत को जीवनशैली का हिस्सा बनाएं, तो इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। संयम का अर्थ केवल त्याग नहीं होता, बल्कि दूरदर्शिता और जिम्मेदारी भी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील इसी जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित प्रतीत होती है। उन्होंने किसी प्रकार की जबरदस्ती या प्रतिबंध की बात नहीं की, बल्कि नागरिकों से स्वैच्छिक सहयोग की अपेक्षा की। यह लोकतांत्रिक नेतृत्व की पहचान है।

एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री का कर्तव्य केवल संकट आने पर कदम उठाना नहीं होता, बल्कि संकट के संकेतों को पहचानकर समय रहते जनता को तैयार करना भी होता है। आज जब दुनिया के कई देशों में आर्थिक अस्थिरता के कारण भारी महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव देखने को मिल रहे हैं, तब भारत अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति में है। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में अपनाई गई आर्थिक नीतियों, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत अभियान और वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत स्थिति का परिणाम है। यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वव्यापी संकटों के बावजूद भारत ने अपने नागरिकों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया। महामारी से लेकर युद्धजनित परिस्थितियों तक भारत सरकार ने लगातार राहत योजनाएं चलाईं, गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया, किसानों और मध्यम वर्ग को विभिन्न प्रकार की सहायता दी तथा अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए। वैश्विक मंदी और युद्ध के वातावरण में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल बना हुआ है। यह प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रमाण है।

दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि देशहित के ऐसे विषयों पर भी कुछ राजनीतिक दल संकीर्ण राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे। लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार सभी को है, लेकिन हर विषय को राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू में तौलना राष्ट्रहित के विरुद्ध है। यदि प्रधानमंत्री जनता से संयम की अपील करते हैं तो विपक्ष को चाहिए कि वह भी जनता को जागरूक करे, न कि भय और भ्रम का वातावरण बनाए। राजनीति तब तक स्वस्थ मानी जाती है जब तक वह राष्ट्रहित से जुड़ी रहे। लेकिन जब राजनीति केवल विरोध के लिए विरोध करने लगे और राष्ट्रीय संकटों को भी अवसर की तरह देखने लगे, तब वह लोकतंत्र को कमजोर करती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरा देश एक परिवार की तरह सोचते हुए राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माने। संकट के समय संयम, अनुशासन और सहयोग ही किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। भारत ने इतिहास में अनेक बार यह सिद्ध किया है कि जब भी राष्ट्र पर संकट आया, भारतीय समाज ने अद्भुत त्याग और एकता का परिचय दिया। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर युद्धकाल तक, भारतीय जनता ने अपने निजी हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को महत्व दिया है। आज फिर वही समय है जब हमें समझना होगा कि अनावश्यक उपभोग, दिखावे की प्रवृत्ति और अंधाधुंध विलासिता अंततः देश की आर्थिक मजबूती को कमजोर करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को इसी व्यापक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। यह केवल सोना न खरीदने या ईंधन बचाने का संदेश नहीं, बल्कि आत्मसंयम, आत्म अनुशासन और राष्ट्रीय जिम्मेदारी का संदेश है। भारतीय संस्कृति का मूल स्वर भी यही रहा है कि व्यक्ति अपने आचरण से समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाए। यदि हम संयम को जीवन का हिस्सा बना लें तो अनेक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान स्वतः संभव हो सकता है। आज दुनिया जिस अनिश्चितता और संकट के दौर से गुजर रही है, उसमें भारत अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में खड़ा है। इसका श्रेय देश की जनता की सामर्थ्य के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भी जाता है। ऐसे समय में आवश्यकता राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सकारात्मक सोच की है। संयम केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माण का आधार है। यदि हम इस भावना को समझ सकें, तो न केवल वर्तमान संकटों का सामना कर पाएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकेंगे।

दिल्ली में सजेगा 'भारतीय व्यापार महोत्सव' का महामंच

@ राष्ट्र समाज

राजधानी नई दिल्ली का प्रगति मैदान स्थित 'भारत मंडपम' एक बार फिर देश के सबसे बड़े व्यापारिक मंथन का गवाह बना। गत 18 और 19 मई को यहां दो दिवसीय एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 12 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाले ऐतिहासिक 'भारतीय व्यापार महोत्सव' की तैयारियों की समीक्षा करना था। 'कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' के तत्वावधान में होने वाला यह महोत्सव देश के व्यापारिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इस दो दिवसीय बैठक के पहले ही दिन यानी 18 मई को इस महोत्सव की आधिकारिक वेबसाइट को भी लांच किया गया, जो डिजिटल इंडिया के दौर में देश भर के व्यापारियों को एक मंच पर लाने का काम करेगी।

वेबसाइट लॉन्चिंग के इस पावन और बड़े अवसर पर भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने अपने कर-कमलों से वेबसाइट को लांच करते हुए कैट की इस अनूठी पहल की जमकर सराहना की। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री

पीयूष गोयल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में छोटे और बड़े व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मौजूद सभी पदाधिकारियों और व्यापारियों का उत्साहवर्धन किया और भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर देश के व्यापारिक समुदाय के साथ खड़ी है।

राम गोपाल बंशाल और सांसद प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में मिली बड़ी सफलता

किसी भी बड़े आयोजन की रीढ़ उसकी कोर टीम होती है। इस दो दिवसीय समीक्षा बैठक की अभूतपूर्व सफलता के पीछे कैट के राष्ट्रीय महासचिव और चांदनी चौक लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी का कुशल नेतृत्व रहा। उनके मार्गदर्शन में पहले दिन की बैठक बेहद सकारात्मक और भावी रणनीतियों को तय करने वाली रही। इस ऐतिहासिक व शुभ अवसर पर 'भारतीय व्यापार महोत्सव' के ऑर्गेनाइजिंग बोर्ड के चेयरमैन राम गोपाल बंशाल भी विशेष रूप से शामिल हुए। चेयरमैन होने के नाते उन्होंने महोत्सव के ले-आउट, व्यापारियों की भागीदारी और चार दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर विस्तृत चर्चा की।

12 से 15 अगस्त तक दिखेगी भारतीय व्यापार की ताकत

यह महोत्सव देश की आजादी के जश्न (15 अगस्त) के साथ आयोजित हो रहा है, जो इसे और भी ज्यादा खास बना देता है। भारत मंडपम में जुटने वाली यह व्यापारिक महापंचायत न सिर्फ भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक के व्यापारिक गठजोड़ का एक नया रास्ता भी खोलेगी।

BTW

Delivering Taste, Quality & Legacy

AT EVERY STEP

RETAIL

As a pure vegetarian restaurant, we serve a wide variety of multi-cuisine dishes and are especially known for our chaat and snacks. We operate 20 QSR outlets across Delhi NCR and Mohali. Our stores also offer a comprehensive selection of sweets and gifting options.

FMCG

Our FMCG range has over 1000 SKUs, available across major modern outlets, e-commerce platforms, army canteens, and police canteens. We also manufacture material for several esteemed brands through private labelling, like Unibic, Big Basket, Vishal Mega Mart etc.

CATERING

We are one of India's largest Chaat caterers and offer catering services across the globe. On average, we serve around 75 functions each wedding season, maintaining our quality and legacy at every event.

For More Information

01164646464 | customercare@btwindia.com | www.btwindia.com

@ संजय सक्सेना

नेशन फर्स्ट पर आगे बढ़ता नेपाल

नेपाल की राजनीति इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। इस बदलाव से उसके चीन और भारत जैसे पड़ोसी नाराज होते हैं तो इसकी चिंता नेपाल को शायद नहीं है। नेपाल पूरी तरह से नेशन फर्स्ट पर चल रहा है। काठमांडू की सत्ता अब पहले की तरह भारत पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से निर्भर रहने के पक्ष में नहीं दिखती। प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिनसे यह साफ संकेत जाता है कि नेपाल अब 'नेपाल प्रथम' की नीति पर आगे बढ़ना चाहता है। यही वजह है कि व्यापार, सीमा, कस्टम ड्यूटी और चीन के साथ रिश्तों जैसे मुद्दे अब नेपाल की घरेलू राजनीति और राष्ट्रवाद का हिस्सा बन चुके हैं। भारत के लिए चिंता केवल नेपाल के कुछ फैसले नहीं हैं, बल्कि वहां तेजी से बदलती राजनीतिक सोच है। नेपाल और भारत के बीच करीब 1850 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के आवाजाही करते हैं। अनुमान है कि हर दिन 50 हजार से ज्यादा लोग रोजगार, व्यापार, शिक्षा और पारिवारिक कारणों से सीमा पार करते हैं। नेपाल के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 64 प्रतिशत हिस्सा भारत के साथ होता है। 2025-26 में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा असंतुलन यह है कि नेपाल ने भारत से करीब 11 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जबकि उसका निर्यात केवल 2 अरब डॉलर के आसपास रहा। यही लगभग 9 अरब डॉलर का व्यापार घाटा अब नेपाल की नई राष्ट्रवादी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है।

नेपाल के उद्योग परिसंघ और आर्थिक विशेषज्ञों का एक वर्ग लगातार यह दावा करता रहा है कि भारतीय बाजार से आने वाले सस्ते उत्पादों ने नेपाली उद्योगों को कमजोर कर दिया। कपड़ा उद्योग, कृषि आधारित कारोबार और छोटे विनिर्माण क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इसी सोच के तहत बालेन शाह सरकार ने भारत से नेपाल लाए जाने वाले 100 नेपाली रुपये से अधिक कीमत के सामान पर कस्टम ड्यूटी

लगाने का फैसला किया। सरकार का कहना था कि इससे घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिलेगा और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इस फैसले का असर सीधे सीमा क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला था। वीरगंज, विराटनगर, नेपाल गंज और भैरहवा जैसे शहरों में हजारों छोटे व्यापारी भारतीय बाजारों से राशन, कपड़े, दवाइयां और घरेलू सामान खरीदकर नेपाल ले जाते हैं। व्यापारियों का अनुमान था कि नई ड्यूटी व्यवस्था लागू होने के बाद रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती थी। नेपाल पहले ही महंगाई और बेरोजगारी के दबाव से जूझ रहा है। विश्व बैंक के अनुसार नेपाल में युवा बेरोजगारी दर 20 प्रतिशत से ऊपर है। ऐसे में यह फैसला आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला माना गया।

नेपाल के भीतर इस फैसले का विरोध शुरू हो गया। व्यापारी संगठनों और सीमा-पार कारोबारियों ने इसे अव्यावहारिक बताया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए टैक्स वसूली पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि सरकार को सीमा क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना होगा। अदालत के इस हस्तक्षेप ने साफ कर दिया कि नेपाल में राष्ट्रवादी राजनीति तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसकी सीमाएं अब भी संवैधानिक संस्थाएं तय कर रही हैं। दरअसल नेपाल में भारत को लेकर असहजता कोई नई बात नहीं है। 2015 में नेपाल के नए संविधान को लेकर पैदा हुए विवाद और उसके बाद सीमा पर आपूर्ति बाधित होने की घटनाओं ने भारत-विरोधी भावना को गहरा किया। उस समय नेपाल में पेट्रोल, गैस और दवाइयों की भारी कमी हो गई थी। नेपाल के भीतर बड़ी संख्या में लोग आज भी मानते हैं कि उस दौर में भारत ने दबाव की राजनीति अपनाई थी। उसी समय के बाद 'आर्थिक आत्मनिर्भरता' और 'राष्ट्रीय सम्मान' जैसे मुद्दे तेजी से लोकप्रिय हुए।

बालेन शाह ने इसी भावना को राजनीतिक ताकत में बदला। नेपाल की लगभग 42 प्रतिशत आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है और यही युवा वर्ग सोशल मीडिया आधारित राष्ट्रवादी राजनीति से तेजी से प्रभावित हो रहा है। नेपाल में भारत के साथ आर्थिक निर्भरता कम करने और 'स्वतंत्र विदेश नीति' की मांग लगातार बढ़ रही है। कई राष्ट्रवादी समूह भारत के साथ सीमा नियंत्रण सख्त करने की बात भी खुले तौर पर कर रहे हैं। हालांकि नेपाल केवल भारत से दूरी बनाकर चीन के करीब जाता हुआ भी नहीं दिखना चाहता। चीन की बेल्ट एंड रोड

परियोजना के तहत नेपाल में सड़क, रेलवे और ऊर्जा परियोजनाओं में लगभग 8 अरब डॉलर तक के निवेश प्रस्तावित हैं। नेपाल सरकार अब इन परियोजनाओं की लागत और ऋण शर्तों की समीक्षा कर रही है। काठमांडू में यह डर मौजूद है कि अत्यधिक चीनी कर्ज नेपाल को आर्थिक रूप से कमजोर कर सकता है। इसके बावजूद चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और मशीनरी के क्षेत्र में चीन नेपाल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन चुका है।

दूसरी तरफ नेपाल यह भी समझता है कि भारत से पूरी दूरी बनाना उसके लिए संभव नहीं। नेपाल की पेट्रोलियम जरूरतों का लगभग पूरा हिस्सा भारत से आता है। समुद्री व्यापार के लिए नेपाल पूरी तरह भारतीय बंदरगाहों पर निर्भर है। नेपाल के लाखों नागरिक रोजगार के लिए भारत आते-जाते हैं। दोनों देशों के बीच पारिवारिक और सांस्कृतिक रिश्ते इतने गहरे हैं कि उन्हें केवल राजनीतिक फैसलों से खत्म नहीं किया जा सकता। दिल्ली भी इस बदलते नेपाल को लेकर सतर्क है। भारत समझता है कि केवल ऐतिहासिक रिश्तों के भरोसे अब नेपाल में अपना प्रभाव बनाए रखना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि हाल के वर्षों में भारत ने नेपाल में रेलवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन, बिजली ट्रांसमिशन और डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर तेजी से निवेश बढ़ाया है। नेपाल ने 2025-26 में भारत को लगभग 1000 मेगावाट बिजली निर्यात की, जिससे उसे करीब 15 अरब नेपाली रुपये की आय हुई। फिलहाल नेपाल की राजनीति ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां राष्ट्रवाद सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया है। लेकिन आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या 'नेपाल प्रथम' की यह नीति नेपाल को आर्थिक रूप से मजबूत बना पाएगी या फिर भारत जैसे सबसे बड़े साझेदार से लगातार बढ़ता तनाव उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगा। भूगोल व इतिहास की सच्चाई यही है कि भारत व नेपाल चाहे जितनी राजनीतिक दूरी बनाने की कोशिश करें, दोनों देशों का भविष्य भी एक-दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है।

शिवालिक की गोद में बसा हरियाणा का इकलौता हिल स्टेशन

@ राष्ट्र समाज

जब भी भारत के खूबसूरत हिल स्टेशंस की बात होती है, तो अमूमन लोगों के जेहन में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या कश्मीर के नाम उभरते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैदानी इलाकों और संपन्न खेती के लिए मशहूर हरियाणा के पास भी अपनी गोद में छुपा हुआ एक बेहद खूबसूरत और शांत पर्वतीय कोना है। हरियाणा के पंचकूला जिले में स्थित 'मोरनी हिल्स' राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है। हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला की गोद में, समुद्र तल से करीब 1,220 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह क्षेत्र अपनी बेदाग प्राकृतिक सुंदरता, रहस्यमयी झीलों और समृद्ध पुरातात्विक इतिहास के लिए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

यदि आप दिल्ली-एनसीआर या पंजाब-हरियाणा के चक्रव्यूह से निकलकर वीकेंड पर किसी शांत, हसीन और ऐतिहासिक जगह की तलाश में हैं, तो मोरनी हिल्स एक मुफीद मुकाम है। आइए, मासिक पत्रिका के इस विशेष अंक में करीब से जानते हैं मोरनी हिल्स के इतिहास, इसकी विरासत और यहाँ छिपे कुदरत के अनूठे रहस्यों को।

रानी मोरनी की विरासत

मोरनी हिल्स का इतिहास जितना खूबसूरत है, उतना ही दिलचस्प इसका नामकरण भी है। स्थानीय लोककथाओं और मान्यताओं के अनुसार, इस पर्वतीय क्षेत्र का नाम 'मोरनी' किसी पक्षी के नाम पर नहीं, बल्कि एक रानी के नाम पर पड़ा था। माना जाता है कि लगभग दो हजार साल पहले इस पूरे पहाड़ी इलाके पर 'रानी मोरनी' का शासन था। वह एक बेहद न्यायप्रिय, साहसी और प्रजा-हितैषी शासक थीं। उनके जाने के सदियों बाद भी स्थानीय लोगों के दिलों में उनके प्रति सम्मान कम नहीं हुआ और उन्हीं की याद में इस पूरे क्षेत्र को 'मोरनी हिल्स' कहा जाने लगा।

राजपूत, चन्देल और मुगलों का प्रभावः यह शांत दिखने वाला हिल स्टेशन पुरातात्विक और ऐतिहासिक रूप से बेहद समृद्ध है। इतिहास की परतें पलटें तो पता चलता है कि इस क्षेत्र पर समय-समय पर राजपूत, चंदेल और मुगलों जैसे शक्तिशाली राजवंशों का प्रभाव रहा है। मोरनी के 'ठाकुरद्वारा मंदिर' के खंडहर और अवशेष इस बात की गवाही देते हैं कि यह क्षेत्र 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ से प्राप्त प्राचीन मूर्तियां और नक्काशीदार पत्थर इतिहासकारों के लिए आज भी शोध का विषय हैं। ऐतिहासिक काल में यह पूरा इलाका कोटाहा के राजा और पिंडरावल के राजा मीर सैयद मुहम्मद बाकर अली खान की जागीर का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था की बात करें, तो यहाँ मुख्य रूप से कंनेट्स, गौड़ ब्राह्मण और गुर्जर समुदाय के लोग निवास करते थे, जो पहाड़ों की ढलानों पर निर्वाह कृषि (सीढ़ीदार खेती) के जरिए अपना जीवन-यापन करते थे।

मोरनी गांव में कदम रखते ही इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है यहां का 200 साल पुराना 'मोरनी किला'। यह किला कभी इस क्षेत्र की सामरिक और प्रशासनिक शक्ति का केंद्र हुआ करता था। समय के थपेड़ों को झेलते हुए जब यह ऐतिहासिक धरोहर जीर्ण-शीर्ण होने लगी, तब हरियाणा सरकार और पर्यटन विभाग ने एक सराहनीय पहल की। सरकार ने इस प्राचीन किले का जीर्णोद्धार कर इसे एक बेहद खूबसूरत 'प्रकृति संग्रहालय और अध्ययन केंद्र' के रूप में विकसित कर दिया है, जहाँ आने वाले पर्यटक इस क्षेत्र की जैव-विविधता और इतिहास से रूबरू हो सकते हैं।

मोरनी गांव में कदम रखते ही इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है यहां का 200 साल पुराना 'मोरनी किला'। समय के थपेड़ों को झेलते हुए जब यह ऐतिहासिक धरोहर जीर्ण-शीर्ण होने लगी, तब हरियाणा सरकार और पर्यटन विभाग ने एक सराहनीय पहल की।

मोरनी हिल्स केवल पहाड़ों के लिए नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमयी झीलों के लिए भी प्रसिद्ध है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, यहाँ दो मुख्य झीलें हैं जो एक छोटी पहाड़ी से आपस में अलग होती हैं। लेकिन प्रकृति का चमत्कार देखिए–इन दोनों झीलों का जल स्तर हमेशा एक समान रहता है। स्थानीय लोगों और भूगर्भशास्त्रियों का मानना है कि इन दोनों झीलों के बीच धरती के नीचे कोई छिपा हुआ भूमिगत चैनल है, जो दोनों के पानी को आपस में जोड़े रखता है। स्थानीय समाज में इन झीलों को बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इन झीलों से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है 'टिक्कर ताल'। टिक्कर ताल असल में दो खूबसूरत झीलों का समूह है, जिसे हरियाणा पर्यटन विभाग ने एक शानदार टूरिस्ट स्पॉट के रूप में पुनर्जीवित किया है। हरे-भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरी यह झील पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।

मॉडर्न टूरिज्म का नया हब

आज का मोरनी हिल्स सिर्फ शांति खोजने वाले बुजुर्गों या इतिहास प्रेमियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं के लिए एडवेंचर का नया ठिकाना बन चुका है। हरियाणा पर्यटन विभाग यहाँ पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रसिद्ध 'माउंटेन क्वेल' रिसॉर्ट का संचालन करता है, जहाँ ठहरने और लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाने की बेहतरीन व्यवस्था है। इसके अलावा, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यहाँ एक आधुनिक 'एडवेंचर पार्क' का निर्माण किया है। यहाँ आने वाले युवा और बच्चे ज़िपलाइन, रॉक क्लाइंबिंग, बर्मा ब्रिज और घने जंगलों के बीच ट्रेकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए भी यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ शिवालिक की दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं।

यदि आप भी दिल्ली, चंडीगढ़ या देश के किसी भी कोने से मोरनी हिल्स की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ठहरने की बुकिंग और अन्य सुविधाओं की सटीक जानकारी के लिए हरियाणा पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बदलते दौर में जहाँ शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशन पर्यटकों की भारी भीड़ और कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो रहे हैं, वहीं मोरनी हिल्स आज भी अपनी शुद्ध हवा, शांत वादियों और ऐतिहासिक गौरव को समेटे हुए है। यह स्थान इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे प्रकृति और इतिहास एक साथ मिलकर किसी जगह को जादुई बना सकते हैं।

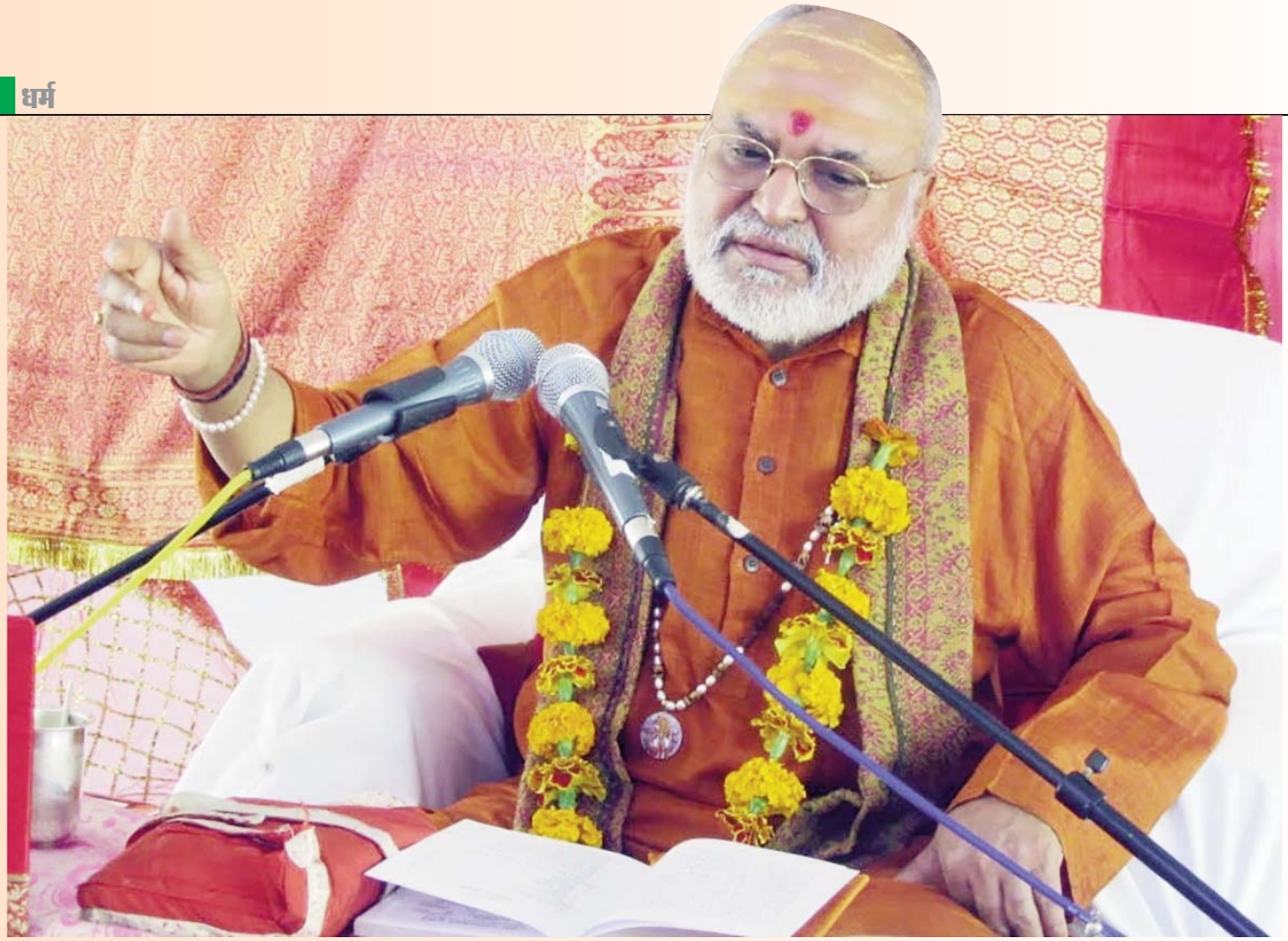

हृदय से उपजे विचार ही बदल सकते हैं समाज की दिशा: स्वामी सवार्नंद सरस्वती

@ राष्ट्र समाज

आज का आधुनिक समाज जिस अंधाधुंध रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वह बाहर से जितना चमकदार दिखता है, भीतर से उतना ही खोखला होता जा रहा है। मनुष्य ने भौतिक तरक्की के नए आयाम तो छू लिए हैं, लेकिन इस दौड़ में उसके नैतिक और मानवीय मूल्य कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। आज का संपूर्ण परिवेश इंसानी इच्छाओं के प्रदूषण से ग्रसित है। चारों ओर एक अजीब सी होड़ मची है, दूसरों से आगे निकलने की, सब कुछ अपने नाम कर लेने की। इस वैचारिक और आत्मिक संकट के बीच 'अंतर्राष्ट्रीय भजन सुखसेवा मिशन' ने संपूर्ण मानवता को झकझोरने वाला एक बेहद जरूरी और सामयिक संदेश दिया है, 'ईश्वर को अपना मार्ग दर्शक बनने दें' मिशन के इसी पावन उद्देश्य को रेखांकित करते हुए परम पूजनीय स्वामी सवार्नंद सरस्वती जी ने वर्तमान समय में इंसान के गिरते आचरण, मन और हृदय के द्वंद्व और इसके शाश्वत समाधान पर अत्यंत गहराई से

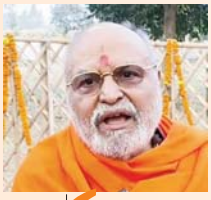

आज इंसान 'हृदय' की निर्मलता को छोड़कर केवल 'मन' की चालाकियों से काम ले रहा है। मन से किया गया हर कार्य स्वार्थ से भरा होता है, जबकि हृदय से उपजे विचार करुणा, दया और निस्वार्थ भाव से परिपूर्ण होते हैं। यदि हम समाज और राष्ट्र को बदलना चाहते हैं, तो इसकी शुरूआत अपने घर से करें। अपने शब्दों को मधुर और छल-रहित बनाएं, तभी जीवन में वास्तविक सुख और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा।

स्वामी सवार्नंद सरस्वती जी
महराज

प्रकाश डाला है। यह आलेख आज के भटके हुए समाज के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका की तरह है।

दूषित होता वातावरण

स्वामी जी का कहना है कि आज का वातावरण किसी बाहरी प्रदूषण से उतना गंदा नहीं हुआ है, जितना मनुष्य की दिवास्वप्न भरी अतृप्त इच्छाओं, पाखंड और अहंकार के कारण दूषित हुआ है। भ्रम की परतों में डूबा और भ्रामक विचारों से चिपका हुआ आज का मानव केवल अपने अपवित्र उद्देश्यों की पूर्ति में दिन-रात लगा हुआ है। इस स्वार्थपरता का सबसे दुखद पहलू यह है कि इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए पवित्र शब्दों का भी सौदा कर लिया है। प्रेम, निष्ठा, सत्यनिष्ठा और सच्चाई जैसे शब्द आज केवल मंचों पर भाषण देने या किताबों में छापने के काम आ रहे हैं। व्यावहारिक जीवन में मनुष्य ने इन शब्दों का दुरुपयोग करते हुए बेईमानी, चालाकी और मिलावट से भरे वाक्यों का एक ऐसा जाल बुन लिया है, जिसमें वह खुद ही फंसता चला जा रहा है। दूसरों के प्रति घृणा, ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखकर मनुष्य किसी और का नहीं, बल्कि खुद अपना ही विनाश कर रहा है।

जैसा बोओगे, वैसा काटोगे

इस संसार का एक शाश्वत नियम है, कर्म का सिद्धांत। स्वामी जी बड़े ही सरल शब्दों में समझाते हैं कि प्रकृति का यह नियम कभी नहीं बदलता कि 'आप जैसा बोओगे, वैसा ही काटोगे।' यदि हम बबूल का पेड़ लगाकर आम के फल की इच्छा करेंगे, तो वह कभी पूरी नहीं हो सकती। आज के समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हर व्यक्ति यह चाहता है कि दूसरे उसके साथ प्रेम, आदर और ईमानदारी का व्यवहार करें, लेकिन जब खुद व्यवहार करने की बारी आती है, तो वह स्वार्थ और चालाकी का सहारा लेता है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि आप वास्तव में आंतरिक शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो दूसरों से जो अपेक्षा रखते हैं, वैसा ही व्यवहार पहले दूसरों के साथ करना शुरू कीजिए। यही शांति का एकमात्र मार्ग है।

चालाकी और निर्मलता का द्वंद्वः स्वामी सवार्नंद सरस्वती जी ने आज के परिवेश का एक अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया है। आज के समाज में 'हृदय' का महत्व लगातार कम होता जा रहा है, जबकि तथाकथित 'मानसिक या बौद्धिक आवेग' अधिक हावी दिखाई देता है। लोग हर बात में नफा-नुकसान, गणित और चालाकी ढूंढते हैं। हमें यह समझना होगा कि केवल मन या बुद्धि से किया गया कोई

भी कार्य स्वार्थ की संकीर्ण भावना से भरा होता है। मन चंचल है, वह केवल अपनी सुख-सुविधा देखता है। इसके विपरीत, जो कार्य हृदय से किया जाता है, वह पूरी तरह निर्मल भावों, करुणा और दयालु भावनाओं से परिपूर्ण होता है। हृदय से निकला हर कार्य ईश्वर की सुंदर रचना का हिस्सा बन जाता है।

हृदय का तार सीधे तौर पर 'सच्चिदानंद' (सत-चित-आनंद) यानी उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है। जो मनुष्य विषम परिस्थितियों में भी अपने सत्य पर अटल रहता है, वही वास्तव में 'हृदय-प्रधान' मनुष्य है। ऐसा व्यक्ति समय, आत्मा और संयम के गुणों का आदर करता है।

बदलाव की शुरूआत अपने घर से करेंः मी जी का यह संदेश केवल उपदेश नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन पद्धति है। वर्तमान समय की सबसे बड़ी और अनिवार्य आवश्यकता है, सद्गुणपूर्ण और हृदय-उन्मुख आचरण। दुनिया में जितने भी दुख, क्लेश और युद्ध हैं, उन सब की जड़ में कहीं न कहीं निर्दयता छिपी हुई है। यदि हम वास्तव में दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो इसकी शुरूआत हमें किसी वैश्विक मंच से नहीं, बल्कि अपने घर से करनी होगी।

अपने घर के वातावरण को अपने दयालु प्रयासों, कोमलता और बिना किसी छल-कपट वाले मधुर शब्दों से सुगंधित करें। जब आपके घर में प्रेम और दया का वास होगा, तो उसकी खुशबू आपके पड़ोस, आपके गाँव, आपके कस्बे, आपके शहर और अंततः आपके पूरे देश को हमारी महान भारतीय आध्यात्मिक नींव से आलोकित कर देगी। यही वह मार्ग है जो मनुष्य के लिए मोक्ष और ईश्वर के शाश्वत, अनंत साम्राज्य का द्वार खोलता है।

मोदी सरकार के 12 साल: भारत की अद्भुत गौरवशाली विकास यात्रा

@ डॉ. अर्चना गुप्ता
प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा हरियाणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों ने भारत की विकास यात्रा को नई दिशा, नई गति और नया आत्मविश्वास प्रदान किया है। वर्ष 2014 में शुरू हुआ यह सफर केवल सरकार बदलने का नहीं था, बल्कि शासन की कार्यशैली, विकास की प्राथमिकताओं और जनकल्याण की सोच में व्यापक परिवर्तन का था। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के साथ केंद्र सरकार ने देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया और भारत को एक सशक्त, आत्मनिर्भर तथा आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए। इन 12 वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक, सामरिक और तकनीकी क्षेत्रों में अनेक नई उपलब्धियां हासिल की हैं। देश आज दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया और पीएम गति शक्ति जैसी पहलों ने विकास को नई ऊर्जा प्रदान की है। यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने भारत को डिजिटल क्रांति का वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाया है, जबकि चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत की वैज्ञानिक क्षमता का परचम पूरे विश्व में लहराया है।

मोदी सरकार की विकास यात्रा का सबसे बड़ा आधार मजबूत आधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण रहा है। देशभर में रिकॉर्ड संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेलवे लाइनें, एयरपोर्ट और बंदरगाह विकसित किए गए हैं। वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और माल परिवहन के लिए समर्पित गलियारों का निर्माण भारत की आर्थिक प्रगति को नई गति दे रहा है।

हरियाणा भी इस परिवर्तनकारी विकास यात्रा का प्रमुख भागीदार बना है। केंद्र की मोदी सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार के समन्वित प्रयासों ने राज्य को आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक प्रगति के नए शिखरों तक पहुंचाया है। केंद्र द्वारा राज्यों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए ऐतिहासिक निर्णयों का हरियाणा को विशेष लाभ मिला है। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ने से हरियाणा को विकास परियोजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हुए, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में आधारभूत संरचना और जनकल्याण कार्यक्रमों को नई गति मिली।

रेलवे क्षेत्र में हरियाणा ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य का संपूर्ण रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है तथा अनेक नई रेल परियोजनाओं पर कार्य जारी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इसी प्रकार गुरुग्राम सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूत बना रहा है। सड़क और एक्सप्रेसवे निर्माण के क्षेत्र में हरियाणा आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं न केवल यातायात को सुगम बना रही हैं, बल्कि निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रही हैं। इन परियोजनाओं ने हरियाणा को देश की आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। फरीदाबाद में अत्याधुनिक अमृता अस्पताल, रेवाड़ी में एम्स और झज्जर में स्वास्थ्य एवं योग से संबंधित संस्थानों की स्थापना ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को नई ऊंचाई दी है। वहीं आयुष्मान भारत योजना ने लाखों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की है। कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी मोदी सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता मिल रही है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने का अभियान जीवन स्तर में सुधार का माध्यम बना है। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है, जबकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने लाखों युवाओं और छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। जनधन योजना, मुफ्त राशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने गरीब और वंचित वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। पहली बार विकास और जनकल्याण योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचा है। यही कारण है कि सरकार के प्रति जनता का विश्वास निरंतर मजबूत हुआ है। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के क्षेत्र में भी इन 12 वर्षों का विशेष महत्व है।

अनुच्छेद 370 का निरसन, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, जी-20 की सफल अध्यक्षता तथा भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा इस बात के प्रमाण हैं कि देश आज आत्मविश्वास के साथ विश्व मंच पर अपनी भूमिका निभा रहा है। वास्तव में मोदी सरकार के 12 वर्ष केवल विकास के आंकड़ों की कहानी नहीं हैं, बल्कि यह विश्वास, सुशासन और जनसेवा की एक व्यापक यात्रा है। हरियाणा इसका जीवंत उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों ने विकास को जन-जन तक पहुंचाया है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में भारत और हरियाणा नई उपलब्धियों के साथ विकास के नए अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं।

राष्ट्रीय हिन्दी पत्रिका

राष्ट्र समाज

आप की आवाज

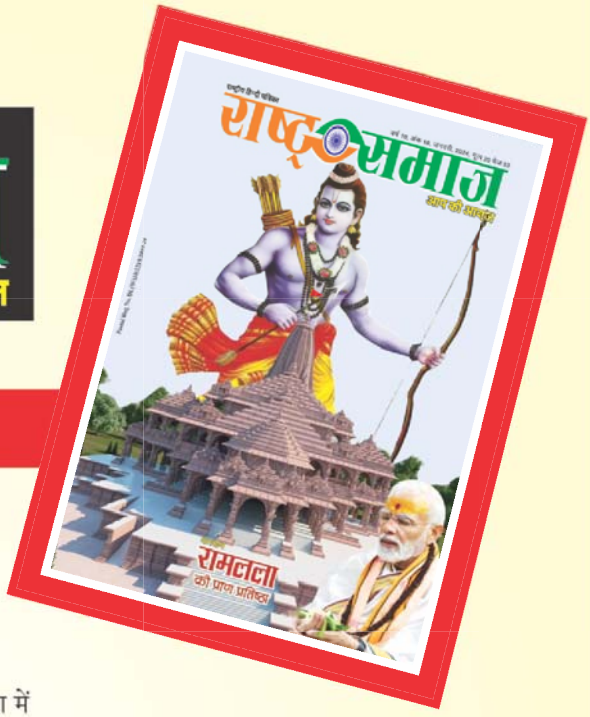

अपने बिजनेस को दें एक नई उड़ान

लगभग एक दशक से भारतीय संस्कृति एवं जीवन मूल्यों के प्रचार-प्रसार में संलग्न राष्ट्रीय समाचार पत्रिका राष्ट्र समाज संपूर्ण रूप से एक पारिवारिक पत्रिका है। इसमें समाचार, विचार व सम सामयिक विषयों पर समीक्षात्मक आलेखों के साथ धर्म, दर्शन व अध्यात्म से जुड़े विषयों का समावेश है। पत्रिका में नियमित रूप से राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक, साहित्य, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल, मनोरंजन व राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित जनोपयोगी व रुचिकर सामग्री प्रकाशित की जाती है। अपने पत्रकारीय दायित्वों को समझते हुए राष्ट्र समाज जहां एक तरह राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रगति को दशार्ता है, वहीं दूसरी तरफ विकास की दौड़ में पिछड़ चुके शोषित व वंचित समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी पुरजोर आवाज देश के सामने बुलंद करता है।

यही कारण है कि राष्ट्र समाज पत्रिका समाज के हर वर्ग में समान रूप से लोकप्रिय है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा व पश्चिम बंगाल समेत उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों के लगभग 35 हजार परिवारों तक राष्ट्र समाज की सीधी पहुंच है जिसे तकरीबन एक लाख से भी अधिक सम्मानित पाठक पढ़ते हैं। इतने बड़े पाठक समुदाय के साथ राष्ट्र समाज उचित भुगतान के साथ विज्ञापन व प्रचार-प्रसार के लिहाज से भी एक सशक्त मंच है।

Advertising Rates

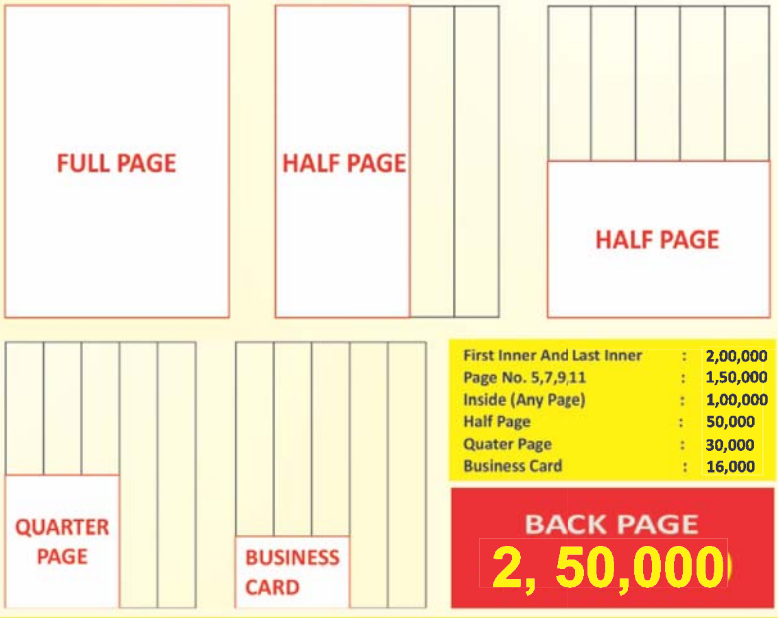

First Inner And Last Inner	:	2,00,000
Page No. 5,7,9,11	:	1,50,000
Inside (Any Page)	:	1,00,000
Half Page	:	50,000
Quater Page	:	30,000
Business Card	:	16,000

BACK PAGE
2, 50,000

BHIM UPI
BHARAT INTERFACE FOR MONEY UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

Scan using any BHIM UPI enabled APP

RASTRA SAMAJ

242394555001456@cnrb

केनरा बैंक Canara Bank
सिंडिकेट Syndicate

Canara | Bhim | Google Pay | PayTm | Phone Pe

शरवरी और वेदांग के 'मस्कारा' ने इंटरनेट पर मचाया धमाल

इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा का रोमांटिक ट्रैक मस्कारा दर्शकों के दिलों को छूने में कामयाब रहा है और देखते ही देखते साल के सबसे चर्चित गानों में शामिल हो गया है1 करोड़ से अधिक व्यूज और सोशल मीडिया पर 1 लाख से ज्यादा रील्स के साथ मस्कारा इस साल का एक बड़ा वायरल म्यूजिक मोमेंट बनकर उभरा है। फिल्म के एक गीत से आगे बढ़कर यह अब एक डिजिटल फेनोमेनन का रूप ले चुका है। शर्वरी और वेदांग रैना की शानदार केमिस्ट्री से सजा मस्कारा, जिसे महान संगीतकार ए. आर. रहमान ने संगीतबद्ध किया है और जिसके बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं, दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर रहा है। इसकी चुलबुली रोमांटिक भावना, खूबसूरत विजुअल्स और तुरंत जुबान पर चढ़ जाने वाली धुन ने इसे हर प्लेटफॉर्म पर पसंदीदा बना दिया है। गाने ने फैन वीडियोज, डांस ट्रेंड्स और कंटेंट क्रिएटर्स के जरिए सोशल मीडिया पर एक बड़ी लहर पैदा कर दी है, जिससे यह एक सांस्कृतिक ट्रेंड बन गया है। इस सफलता पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए शर्वरी ने कहा,₹मैं हमेशा से बॉलीवुड संगीत की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूं क्योंकि गानों में लोगों की यादों और उनके खास पलों का हिस्सा बनने की अद्भुत क्षमता होती है।

61की उम्र में सेहरा पहनने को तैयार आमिर

बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता आमिर खान एक बार फिर से अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में आ चुके हैं। दरअसल हाल ही में उनको और उनकी गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों के अनुसार 61 साल की उम्र में आमिर खान एक बार फिर से दूल्हा बनने के लिए तैयार हैं और गौरी के साथ में शादी करने जा रहे हैं। आमिर खान और गौरी 5 जुलाई को एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी करने वाले हैं। इस सेरेमनी में दोनों के परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल होंगे और दोनों अपने घर पर एक रजिस्ट्रेशन के अलावा साइनिंग सेरेमनी करके अपने रिश्ते को नाम दे देंगे। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि आमिर खान और गौरी तकरीबन 1 साल से परिवार की तरह ही साथ में रह रहे हैं और खुशहाल जीवन भी जी रहे हैं। अब दोनों इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। आमिर खान ने गौरी के साथ में अपने रिश्ते को लेकर बात की थी और कहा था कि वह खुद को खुश नसीब समझते हैं कि उनकी जिंदगी में गौरी आई है।

42 साल की वो हसीना जो वन नाइट स्टैंड में हो गई थी प्रेग्नेंट

अभिनेता सलमान खान स्टारर फिल्म 'रेडी' ने बुधवार को अपनी रिलीज के 15 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर अभिनेत्री कुब्रा सैत ने फिल्म से जुड़े अपने अनुभव शेयर किए। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे सलमान खान ने उनके रोल में डायलॉग जोड़कर उन्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया था।वीडियो में अभिनेत्री कहती हैं, फिल्म 'रेडी' में ऑडिशन में जाने के लिए मैंने ब्लैक ड्रैस पहनी थी और अनीस बज्मी के ऑफिस में आने और मुझे मंजूरी देने का इंतजार कर रही थी। अभिनेत्री ने आगे बताया, यह ऑडिशन फिल्म 'रेडी' में एक नौकरानी के रोल के लिए था, और मैं इसे लेकर बहुत खुश थी। इस फिल्म को करते समय मुझमें बहुत आत्मविश्वास था, क्योंकि यह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। इससे पहले मैंने कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया था।

अभिनेत्री ने बताया कि कैसे सलमान खान ने उन्हें सेट पर नोटिस किया और उनके किरदार में डायलॉग ऐड किए, जिससे फिल्म में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और निखर गई। अभिनेत्री ने कहा, असल में, फिल्म में मेरे पास कोई डायलॉग नहीं था, लेकिन सलमान सर ने कहा कि क्यों ने इसे एक ऐसी नौकरानी बनाया जाए, जो टूटी-फूटी इंग्लिश में बात करती हो। अनीस बज्मी को यह आइडिया बहुत पसंद आया और इसीलिए फिल्म में मेरे पास डायलॉग हैं। उन्होंने आगे कहा, ₹उस समय हर कोई मुझसे कह रहा था कि मेरा दिमाग खराब हो गया है और मैं 'रेडी' फिल्म में काम करने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावली हो रही हूं। लेकिन सच तो यह है कि अगर मैंने उस समय 'रेडी' फिल्म करने का पागलपन नहीं दिखाया होता, तो आज मैं 'कुकू' नहीं बन पाती। इसलिए कभी किसी काम को छोटा मत समझो; कोई भी रोल छोटा नहीं होता, बस एक्टर की सोच छोटी होती है। यह एक ऐसी सीख है जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगी।

अनुष्का शर्मा ने कर दिया ऐसी चीज का प्रमोशन, आ गई आफत

अध्यात्म मार्ग पर चलने को लेकर अनुष्का शर्मा हर किसी की काफी तारीफें बटोरती हैं। लेकिन इस बार अनुष्का शर्मा भयंकर ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं। अनुष्का शर्मा ने होम्योपैथी ट्रीटमेंट को सपोर्ट करते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की। उनका ये स्टैंड यूजर्स को जरा भी पसंद नहीं आया और अनुष्का शर्मा की आलोचना शुरू कर दी।अनुष्का शर्मा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर रंजन शंकरन और बिजनेसमैन नमिता थापर के बीच हुई बातचीत का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि होम्योपैथी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और डॉ. राजन शंकरन ने उनके स्वास्थ्य और वेलनेस से जुड़े नजरिए को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसके साथ ही अभिनेत्री ने हेल्थ, बैलेंसड लाइफस्टाइल और मेंटल अवेयरनेस को लेकर डॉ. शंकरन की समझ की सराहना की। उनके अनुसार, होम्योपैथी ने उनके व्यक्ति गत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉ. राजन शंकरन ने बातचीत में कहा कि होम्योपैथी को सिर्फ बीमारी का इलाज करने वाली पद्धति नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे पूरे स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली प्रणाली के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तरह होम्योपैथी की भी कुछ सीमाएँ हैं। उनके अनुसार, होम्योपैथी व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान देती है, जिससे उसे बीमारी से ठीक होने में मदद मिलती है।

लिमिट भूलकर को एक्टर करने लगा गंदी हरकतें

प्रिया बापट एक मशहूर अभिनेत्री हैं हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपने को-एक्टर के बर्ताव को लेकर हैरान कर देने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि एक किसिंग सीन के वक्त वह अपनी हद पार कर बैठे थे और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक्ट्रेस के पति को बीच में आना पड़ा। प्रिया बापट ने फिल्म फेयर के साथ में हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि ₹वह मेरी पहली फिल्म थी और उसमें मेरा सिर्फ एक किसिंग सीन ही था। मुझे उस पर जब से मैं स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की तब से डाउट था और कुछ आपत्तियां भी थी। मैं लगातार डायरेक्टर से यही पूछ रही थी कि आपको यह किसिंग सीन क्यों चाहिए। ऐसा नहीं था कि मैं किसिंग सीन के लिए तैयार नहीं थी लेकिन वह उस सीन में जस्टिफाई कैसे करेगा। प्रिया बापट ने आगे बताया कि ₹मुझे ऐसा नहीं लगा कि वह किसिंग सीक्वेंस वहां पर फिट बैठ रहा था।मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे समझा दो तो मैं कर लूंगी। अगर इसमें जरूरत है तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन डायरेक्टर अपनी बात पर अड़े रहे और फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है अपनी शंकाएं दूर करके कर लेते हैं।

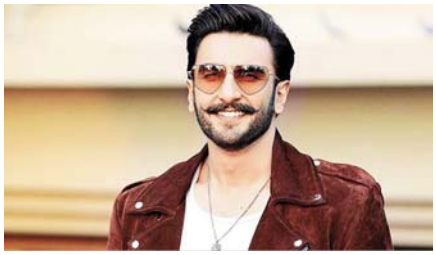

जीत गए रणवीर,एफ डब्ल्यू आईसीई ने हटाया बैन

रणवीर सिंह को लेकर जो हाहाकार फिल्म इंडस्ट्री में मचा हुआ था वो अब टल चुका है। खबरें हैं कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) ने रणवीर पर लगे बैन को हटा दिया है। फरहान अख्तर के साथ डॉन 3 वाले विवाद के बाद एफडब्ल्यूआईसीई ने धुरंधर एक्टर को बैन कर दिया था। लेकिन अब वो बैन हट गया है। बता दें कि रणवीर सिंह ने इस बैन के खिलाफ एक्शन लेने का मन बनाया था और वो खुद भी इस मामले को लेकर अदालत पहुंचे थे। रणवीर ने संगठन को कानूनी नोटिस भेजा जिसके बाद ये खबर सामने आ रही है। एफडब्ल्यूआईसीई आज यानि 3 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई बातें इसमें रखी थी। उन्होंने बताया कि अभिनेता के द्वारा नोटिस भेजा गया है और बातों को स्पष्ट रूप से रखने की बात की गई है। रणवीर सिंह पर प्रतिबंध हटाते हुए अशोक पंडित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।

आरईसी को मिला 'एनबीएफसी ऑफ द ईयर' पुरस्कार

मुंबई/गुरुग्राम: आरईसी लिमिटेड को भारत के बुनियादी ढांचे और बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण और मजबूती में कंपनी के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए, तीसरे वार्षिक भारत एनबीएफसी और फिनटेक शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2026 में 'एनबीएफसी ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आलोक कुमार, सीपीएम, आरईसी ने आरईसी क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई की ओर से पुरस्कार समारोह के दौरान प्राप्त किया। यह सम्मान आरईसी की ज़िम्मेदार वित्तपोषण, सतत विकास और परिचालन उत्कृष्टता के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दशार्ता है। यह राष्ट्र निर्माण की पहल में योगदान देने, हितधारकों का विश्वास बनाए रखने और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने के लिए संगठन के अटूट समर्पण को भी रेखांकित करता है। आरईसी ने अभिनव वित्तीय समाधानों और राष्ट्र की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप रणनीतिक निवेशों के माध्यम से भारत के बिजली और बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता करने में लगातार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सम्मान आरईसी के भारत की अग्रणी एनबीएफसी में से एक के रूप में स्थिति को और मजबूत करता है, जो उत्कृष्टता, पारदर्शिता और सतत विकास के लिए समर्पित है।

अब हल्दीराम की नई इकाई हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड एचएसएफपीएल

नई दिल्ली। (हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड (एचएसएफ पीएल) में मनोहर और मधुसूदन अग्रवाल के नेतृत्व वाले दिल्ली-आधारित गुट के पास 56% हिस्सेदारी है। विलय के प्रमुख विवरण: नई इकाई: हल्दीराम स्नैक्स फूड्स (एचएसएफपीएल) दिल्ली गुट (मनोहर/मधुसूदन): 56% हिस्सा। नागपुर गुट (कमल कुमार शिवकिशन अग्रवाल): 44% हिस्सा। मूल्यांकन: यह विलय लगभग बिलियन डॉलर (लगभग 85,000 करोड़) के मूल्यांकन पर हुआ है, जो भारतीय पैकेट बंद खाद्य उद्योग में सबसे बड़ा माना जा रहा है। अन्य भागीदार: इस सौदे के साथ ही सिंगापुर की टेमासेक ने भी कंपनी में 10% हिस्सेदारी खरीदी है। यह विलय दोनों गुटों के एफएमसीजी कारोबार को एक साथ लाता है, जिससे हल्दीराम भारत के पारंपरिक स्नैक्स बाजार में अपनी स्थिति और मजबूत कर सके। हल्दीराम ने अपने दिल्ली और नागपुर स्थित परिचालनों का एचएसएफपीएल में विलय करने का निर्णय किन कारकों के आधार पर लिया, और इससे कंपनी के मूल्यांकन और बाजार स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है? हलदिराम ने अपने दिल्ली और नागपुर स्थित संयंत्रों का हलदिराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड (एचएसएफपीएल) में विलय करने का निर्णय संस्थागत पूंजी आकर्षित करने, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की तैयारी करने, परिचालन में तालमेल स्थापित करने, बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने और ब्रांड को लेकर बनी अस्पष्टता को दूर करने जैसे रणनीतिक लक्ष्यों के लिए लिया था।

भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट में इंडिया-अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बैठक

नई दिल्ली। भारत एनर्जी समिट (बीईएस) 2026 के तीसरे दिन, इंडिया-अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बैठक बुलाई गई, जिसमें पावर सेक्टर में सहयोग को मजबूत करने के लिए मंत्री, राजदूत, सीनियर अधिकारी और ग्लोबल सेक्टर के लीडर एक साथ आए। हाई-लेवल पार्टिसिपेशन में मॉरिशस और मलावी के अफ्रीकी मिनिस्टर्स के साथ-साथ एम्बेसडर, हाई कमिश्नर और परमानेंट सेक्रेटरी शामिल थे। अफ्रीका 50, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, केन्या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (केट्राको), व अफ्रीका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एसोसिएशन (अफिडा) जैसी इंटर नेशनल एजेंसियों व ऑर्गनाइजेशन के जाने-माने लोगों ने बातचीत में हिस्सा लिया। सीईए के चेयरपर्सन ने इंडियन पावर सेक्टर पर एक ब्रीफ जानकारी दी, जिसके बाद अफ्रीकी देशो, केंद्र व हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों के बीच एक बातचीत और चर्चा का सेशन हुआ, जिसमें पावर सेक्टर में सहयोग के मौकों पर फोकस किया गया। कई अफ्रीकी देशों की छोटी बातों में सहयोग और आपसी विकास के तरीकों पर रोशनी डाली गई। इस सेशन को अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) ने नॉलेज पार्टनर और मॉडरेटर के तौर पर सपोर्ट किया। इसने देशों के रिप्रेजेंटेटिव को अपनी नेशनल प्रायोरिटी, चल रही पहल और खास जरूरतों को शेयर करने के लिए एक कीमती प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ भारत के साथ कोलेबोरेशन से स्ट्रेटेजिक वैल्यू मिल सकती है। इससे दोनों क्षेत्रों में पावर सेक्टर की सस्टेनेबल, भरोसेमंद ग्रोथ को आगे बढ़ाने के मकसद से आपसी फायदे वाली पार्टनरशिप की एक जैसी समझ डेवलप हुई। चचाओं में कैपेसिटी बिल्डिंग व इंस्टीट्यूशनल मजबूती पर भी जोर दिया गया, जॉइंट वेंचर और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के जरिए अफ्रीका में मौकों को खोजा गया, भारतीय राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव और अफ्रीकी नेताओं के बीच काम की बातचीत को आसान बनाया गया।

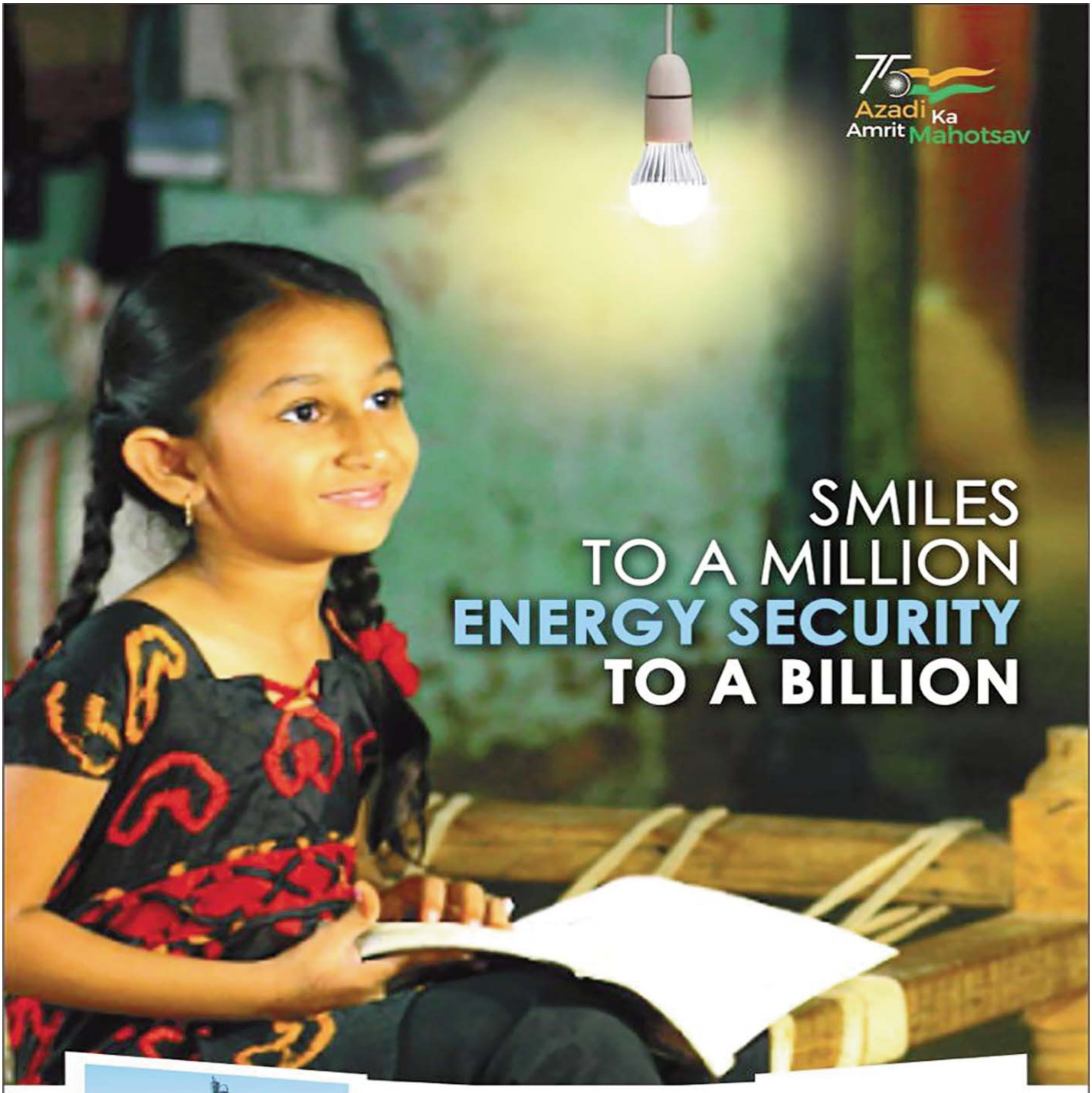

MCL
Enabling Ease of Living...

MAHANADI COALFIELDS LIMITED
(A Govt. of India Undertaking & Subsidiary of Coal India Limited)
Jagruti Vihar, Burla, Dist: Sambalpur-768020 (Odisha)
www.mahanadicoal.in | @mahanadicoal

RNI No.: DELHIN/2014/56304

यूपी का विधाता अन्नदाता

3.12 करोड़ किसानों को
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
₹99 हजार करोड़+
की राशि अंतरित

रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान
₹3.15 लाख करोड़+
गन्ना मूल्य ₹315 से बढ़ाकर
₹400 प्रति क्विंटल

बिचौलिया मुक्त बाजार
ई-मंडी में 6.42 करोड़+ पर्चियां

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
3.53 करोड़+ किसानों
को क्षतिपूर्ति

किसानों को कार्बन क्रेडिट धनराशि वितरित करने वाला
प्रथम राज्य

पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत
86 हजार+
सोलर पंपों की स्थापना

नि:शुल्क बाजार भाव एवं मौसम की जानकारी हेतु
'उत्तर प्रदेश मंडी भाव' मोबाइल ऐप

86 लाख+
लघु/सीमांत किसानों का फसल ऋण माफ

विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश